लखनऊ

शनिवार, 22 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 353

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

आपका दृष्टिकोण ही आपकी दिशा तय करता है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

दिल्ली-एनसीआर में पिछले साल के मुकाबले 6 गुना बढ़े स्वाइन फ्लू के मरीज, सांस की शिकायत

नई दिल्ली। बदलते मौसम के बीच राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एच1एन1 संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी सामने आई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 12 अगस्त तक एच1एन1 के 1,449 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि में सामने आए 229 मामलों की तुलना में करीब छह गुना अधिक है। अकेले 11 अगस्त को 63 नए मामले सामने आए। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संक्रमण का असर आम लोगों के साथ-साथ चिकित्सकों पर भी दिखाई दे रहा है। कई चिकित्सकों और एक सरकारी अस्पताल के प्रमुख के भी एच1एन1 से संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। अस्पतालों में सर्दी-जुकाम और सांस से जुड़ी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए विशेष एवं अलग वार्ड बनाए गए हैं। चिकित्सकों के अनुसार, कुछ मरीजों में सांस लेने में परेशानी और रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि, फिलहाल स्थिति गंभीर स्तर तक नहीं पहुंची है। चिकित्सकों ने लक्षणों को नजरअंदाज न करने और समय पर उपचार लेने की सलाह दी है।

चीनी 2 महीने में 40 प्रतिशत महंगी हुई, अब सरकार ने आयात टैक्स मुक्त किया

नईदिल्ली। देश में चीनी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, यह आयात 31 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। साथ ही देश में चीनी की कमी रोकने के लिए निर्यात पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यह रोक 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी। अधिसूचना के मुताबिक, टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) प्रणाली के तहत 31 अक्टूबर, 2026 तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं द्वारा रखे गए चीनी भंडार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि जो थोक उपभोक्ता प्रति माह 10 टन से ज्यादा चीनी का उपयोग करते हैं, उन्हें 15 दिनों से अधिक की खपत के लिए चीनी का भंडार रखने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने कुछ और नियम बदले हैं। टीआरक्यू के तहत आयात की गई कच्ची चीनी से तैयार रिफाइंड चीनी को 31 अक्टूबर तक घरेलू बाजार में बेचना जरूरी होगा। आयात के समय प्राप्त छूट वाले जीएसटी का भी भुगतान करना होगा। जो थोक खरीदार महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 15 दिन से ज्यादा स्टाक रखने की इजाजत नहीं होगी। पहले ये अनुमति 30 दिन के लिए थी। खुदरा बाजार में चीनी फिलहाल 65 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। एक साल पहले इसी अवधि में यह 46.34 रुपये प्रति किलो थी।

'सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, सिस्टम की नाकामी का भी नतीजा है विरोध'

आरएसएस ने सरकार को दी नसीहत, विशाखापत्तनम बैठक में डेमोग्राफिक बदलाव, युवा चिंता और नशे पर चर्चा

विशाखापत्तनम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने जंतर-मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शनों को केवल भ्रष्टाचार का मामला मानने से इनकार किया है। संघ के नेता सीआर मुकुंदा ने शुक्रवार को कहा कि इन प्रदर्शनों के पीछे व्यवस्था की कुछ व्यापक नाकामियां भी सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। विशाखापत्तनम में संघ की तीन दिवसीय समन्वय समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकुंदा ने कहा कि देश की व्यवस्थाओं में कमियां हैं, लेकिन बदलाव अव्यवस्था या विनाश के रास्ते से नहीं लाया जा सकता।

क्या मामला सिर्फ NEET और भ्रष्टाचार तक सीमित है?

मुकुंदा ने कहा कि युवाओं की चिंताएं केवल नीट या किसी एक सरकार से जुड़ी नहीं हैं। शिक्षा, रोजगार और तेजी से बदलते समाज में युवाओं की आकांक्षाएं भी इस व्यापक चर्चा का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर जो चिंताएं और बेचैनी है, उसे समझने और उसका समाधान करने की जरूरत है। उनके मुताबिक, देश की विभिन्न व्यवस्थाओं में मौजूद कमियों को दूर करना जरूरी है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ था?

कॉकक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 20 जून को जंतर-मंतर पर कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। इसमें नीट से जुड़े आरोप भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर सरकार की जवाबदेही की मांग की थी। सीजेपी का आरोप था कि बार-बार होने वाली परीक्षा संबंधी अनियमितताओं और पेपर लीक ने छात्रों और उनके परिवारों के जीवन को प्रभावित किया है। इस आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेताओं का समर्थन भी मिला। सीजेपी ने 25 जुलाई 2026 को 36 दिन चला अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। संगठन ने दावा किया कि उसकी मांगों को स्वीकार किए जाने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म किया गया।

आरएसएस ने सरकार और समाज से क्या अपील की?

आरएसएस नेता ने कहा कि व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे और समाज को भी जागरूक होकर अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उनके मुताबिक, व्यवस्था में सुधार केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग से भी संभव है।

क्या विरोध से व्यवस्था में बदलाव संभव है?

मुकुंदा ने कहा कि बदलाव अव्यवस्था या विनाश के जरिए नहीं लाया जा सकता। उन्होंने समस्याओं को रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं की चिंताओं को समझना होगा और व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। RSS की बैठक में भी इसी दृष्टिकोण से इन मुद्दों पर चर्चा की गई।

नशे के खिलाफ RSS ने क्या कहा?

देश में ड्रग पेडलिंग से निपटने के सवाल पर मुकुंदा ने कहा कि सरकार इस दिशा में कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी।उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ सामाजिक स्तर पर भी सक्रियता जरूरी है।

दिल्ली में पैलेट गन से घायल युवक के साथ थाने पहुंचे राहुल गांधी, धरने पर बैठे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान चली लाठी और पैलेट गन के मामले में केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष साहिल लोचव के साथ संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने पहुंच गए और मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। बता दें कि साहिल लोचव दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन में घायल हुए थे।

कांग्रेस ने बताया कि 14 अगस्त को साहिल लोचव अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस के पास गए और लिखित शिकायत दी थी।

पुलिस ने जांच अधिकारी का नंबर देने से मना कर दिया। 17 अगस्त को ईमेल और फ़ोन के ज़रिए फिर से कोशिश की गई। फिर भी कोई नंबर नहीं दिया गया। कोई रसीद भी नहीं दी गई।

राहुल भी यही मांग करने पहुंचे थे। उन्होंने इसे एक संज्ञेय अपराध बताकर केस दर्ज करने की मांग की है।

बताया जा रहा है कि साहिल की ओर से शिकायत दर्ज कराने का बाद भी मामले में जांच नहीं की जा रही है। राहुल ने जांच कहां तक बढ़ी और क्या दिक्कत आ रही है, यह पूछने के लिए थाने पहुंचे थे।

पुलिस की ओर से कोई जानकारी न दिए जाने पर राहुल पीड़ित के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया है।

यूपी गैंगस्टर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, दो वकीलों के खिलाफ केस रद्द

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए दो वकीलों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि 1986 का यह कानून अपने आप में कोई अलग आपराधिक अपराध नहीं बनाता है। केवल किसी व्यक्ति को 'गैंगस्टर' घोषित करने के आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाकर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि किसी भी कानून के तहत सजा देने के लिए पहले किसी अपराध का स्थापित होना जरूरी है। पीठ के मुताबिक, यूपी गैंगस्टर एक्ट मुख्य रूप से 'गैंग' और 'गैंगस्टर' की स्थिति को परिभाषित करता है, लेकिन अपने स्तर पर कोई अलग अपराध निर्धारित नहीं करता।

'बिना अपराध के सजा नहीं दी जा सकती'

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस दंड कानून के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है, उसमें किसी अपराध की स्पष्ट परिभाषा और उसके लिए निर्धारित सजा का प्रावधान होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केवल गैंगस्टर की श्रेणी में आने के आधार पर किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत अपराधी नहीं माना जा सकता। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि हिंसा और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाया गया कानून अगर सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तो इसके इस्तेमाल से आम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई का खतरा पैदा हो सकता है।

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की चेतावनी- पाकिस्तान नहीं, लंबे समय में चीन हमारी सबसे बड़ी चुनौती

नईदिल्ली, एजेंसी। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नया और दूरदर्शी आंकलन किया है। अपनी नई किताब के विमोचन पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से खतरा आतंकवाद की वजह से बना रहता है, लेकिन लंबे समय में चीन भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होगा। उन्होंने कहा कि चीन राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार और सैन्य क्षेत्र में मुकाबला करेगा। नरवणे ने यह भी कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। जनरल नरवणे अपनी नई किताब द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइडः अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और चीन दोनों अलग तरह की चुनौतियां हैं। भारत ने दोनों देशों के साथ जंग लड़ी है और दोनों के साथ सीमा विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, इसलिए दोनों देश हमेशा खतरे के तौर पर रडार पर बने रहेंगे। चीन के मामले में चुनौती ज्यादा व्यापक है। नरवणे ने कहा, हमने पाकिस्तान के साथ कई बड़े युद्ध लड़े हैं और आतंकवाद को उनके निरंतर समर्थन के कारण, हमारा ध्यान हमारी पश्चिमी सीमाओं पर केंद्रित है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं कि लंबे समय में और आने वाले वर्षों में चीन हमारा मुख्य प्रतिद्वंद्वी होगा। उन्होंने आगे कहा, और मैंने जानबूझकर प्रतिस्पर्धी शब्द का प्रयोग किया है, न कि दुश्मन शब्द का। नरवणे ने इस बात पर बल दिया कि भारत को ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से चीन के साथ मतभेद सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

जाति का नाम लेना अपराध नहीं, उसके आधार पर अपमानित करना जुर्म है इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ किसी व्यक्ति की जाति का नाम लेने मात्र से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध नहीं बन जाता। अदालत ने कहा कि यह साबित होना भी जरूरी है कि जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से किया गया था। जज संतोष राय ने वेगराज सिंह और एक अन्य की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए बरेली की एक अदालत द्वारा 21 मार्च 2025 को जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। अधीनस्थ अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 358 के तहत दोनों आरोपियों को मुकदमे में शामिल होने के लिए समन भेजा था। 13 अगस्त को दिए अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ चमार शब्द का इस्तेमाल कर देना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि आरोपी ने पीड़िता को उसके अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण अपमानित करने के इरादे से यह शब्द कहा था।

अदालत ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध तय करने के लिए यह भी देखा जाना जरूरी है कि आरोपी के कथित शब्दों और व्यवहार के पीछे जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा थी या नहीं। मामला बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है, जहां दुष्कर्म और धमकी के आरोपों में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मुख्य आरोपी हिम्मत सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। जबकि उसके पिता वेगराज सिंह और बड़े भाई दौलत सिंह को जांच के दौरान आरोपों से बाहर रखा गया था।

जनसंख्या की चरम सीमा पार चुके हैं 64 देश, भारत का ग्राफ अब भी ऊपर..लेकिन कब तक?

2060 के दशक में भारत का पीक संभव है

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया के 64 देश और क्षेत्र अपनी जनसंख्या का पीक पार कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमानों और मीडियम वेरिएंट प्रोजेक्शन के मुताबिक, साल 2026 तक इन देशों की आबादी अपने सबसे ऊंचे आंकड़े को छूकर अब नीचे जाने लगी है। इनमें ज्यादातर यूरोप और पूर्वी एशिया के देश हैं, जहां फर्टिलिटी रेट तेजी से गिरी और फिर लंबे समय तक लो लेवल पर बनी रही। पूर्वी यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर हुए माइग्रेशन ने भी इस गिरावट को और तेज कर दिया।

भारत की तस्वीर फिलहाल इससे अलग है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश का ग्राफ अभी भी ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यह सिलसिला हमेशा नहीं चलने वाला। रिसर्च प्लेटफॉर्म अवर वर्ल्ड इन डेटा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के आधार पर 2060 के दशक तक भारत भी अपने जनसंख्या पीक तक पहुंच सकता है, और उसके बाद यहां भी आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। सवाल अब यह नहीं रह गया कि यह होगा या नहीं, बल्कि यह है कि आखिर कब होगा। अवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक, इस लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया का थाईलैंड, जहां 1990 के दशक की शुरुआत में ही फर्टिलिटी रेट दो बच्चों प्रति महिला से नीचे चली गई थी, अब वहां यह रेट 1.12 से भी कम रह गई है। दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे में भी फर्टिलिटी रेट घटकर औसतन 1.14 बच्चे प्रति महिला रह गई है। इनमें से कई देश हाल ही में अपनी आबादी के पीक को पार कर पाए हैं, लेकिन जापान और इटली जैसे देशों को अपने पीक को पीछे छोड़े एक दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है। स्पेन, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में भी आबादी ने 2010 और 2020 के दशक के बीच अपना सबसे ऊंचा लेवल छू लिया, और अब यह ग्राफ नीचे की ओर मुड़ चुका है।

'शरीर में 200 छर्रे, गंवाई आंख की रोशनी': पीड़ित साहिल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने के बाहर करीब आठ घंटे तक धरने पर बैठने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्र साहिल लोचब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद साहिल लोचब ने राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि पिछले एक महीने से उनकी टीम लगातार उनके संपर्क में थी और राहुल गांधी स्वयं भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहे।

एफआईआर में साहिल लोचब ने आरोप लगाया है कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक निकाले जा रहे छात्र मार्च के दौरान उन पर धातु के पैलेट दागे गए, जिससे उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई और शरीर के कई हिस्सों में सैकड़ों छर्रे लगे।

शिकायत के अनुसार, 20 वर्षीय साहिल लोचब दिल्ली के नजफगढ़ स्थित अग्रवाल कॉलोनी के निवासी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) के छात्र हैं। उन्होंने शिकायत में कहा है कि उनके पिता दिव्यांग हैं और वह परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि उनके खिलाफ कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ।

'क्या आप बस वही कर सकते हैं जो आपका मन करे?'

राहुल गांधी के इस प्रदर्शन पर भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सबसे अहम बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे, वे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की जांच के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाई। इस कमेटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं और इसमें दो अन्य जज, सीबीआई के एक पूर्व डायरेक्टर और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। तो, गोली चली या नहीं, यह खुद ऐसी हाई-पावर्ड कमेटी के सामने जांच का विषय होगा। फिर इन सबका क्या मतलब है? राहुल गांधी, क्या आपको कानून के शासन का कोई सम्मान नहीं है? क्या आप बस वही कर सकते हैं जो आपका मन करे, कहीं भी जा सकते हैं, धरने पर बैठ सकते हैं और अराजकता फैलाना शुरू कर सकते हैं?'

कहां-कहां लगे पैलेट?

एफआईआर के मुताबिक, 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 तथा नीट पेपर लीक के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान संसद की ओर मार्च निकाला जा रहा था। साहिल का कहना है कि लाठीचार्ज और भगदड़ के बीच वह पालिका, कनॉट प्लेस क्षेत्र तक पहुंच गए थे और उनके हाथ में तिरंगा झंडा था।

शिकायत में कहा गया है कि उसी दौरान आंसू गैस और लाठीचार्ज हुआ। इसी बीच उनका चेहरा दूसरी दिशा में था, तभी उन्हें दाहिनी छाती, बाजू और आंख पर तेज धमाके जैसा महसूस हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने नीली वर्दी पहने एक व्यक्ति को बड़ी बंदूक के साथ देखा, जिसने उन पर धातु के पैलेट चलाए। साहिल के अनुसार, उन पर पांच से छह बार पैलेट दागे गए, जिसके बाद उनकी आंख, चेहरा, हाथ और छाती से खून बहने लगा और दाहिनी आंख से दिखाई देना बंद हो गया।

विशाखापट्टनम में होमवर्क न करने पर शिक्षक ने 6 वर्षीय छात्र को थप्पड़ मारा, बच्चे की मौत

विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के एक स्कूल में 6 वर्षीय छात्र की रहस्यमयी मौत ने सबको चौंका दिया है। स्कूल में शिक्षिका ने होमवर्क न करने पर बच्चे को थप्पड़ मारा था, तभी बच्चे की तुरंत मौत हो गई। घटना गुरुवार को वन टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित लिटिल गार्डन प्राइवेट स्कूल में सुबह 11 बजे घटी है। मृतक बच्चा तमन्ना प्रणय तेज यूकेजी का छात्र था। उसके पिता तमन्ना कृष्ण प्रसाद पेशे से रसोइया और मां गृहिणी हैं। प्रणय गुरुवार को स्कूल गया था। यहां महिला शिक्षक बच्चों का होमवर्क चेक कर रही थीं। प्रणय ने शिक्षिका को खाली स्लेट दिखाई, जिसके बाद वह बच्चे को डांटने लगीं। कक्षा में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि शिक्षिका ने बच्चे को अपनी ओर खींचा, उसकी कमीज के बटन खोले और उसे थप्पड़ मारा।

जाति का नाम लेना अपराध नहीं, उसके आधार पर अपमानित करना जुर्म है... इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ किसी व्यक्ति की जाति का नाम लेने मात्र से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध नहीं बन जाता। अदालत ने कहा कि यह साबित होना भी जरूरी है कि जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से किया गया था।

जज संतोष राय ने वेगराज सिंह और एक अन्य की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए बरेली की एक अदालत द्वारा 21 मार्च 2025 को जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। अधीनस्थ अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 358 के तहत दोनों आरोपियों को मुकदमे में शामिल होने के लिए समन भेजा था।

चमार शब्द बोलने मात्र से नहीं बनता अपराध

13 अगस्त को दिए अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ चमार शब्द का इस्तेमाल कर देना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि आरोपी ने पीड़िता को उसके अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण अपमानित करने के इरादे से यह शब्द कहा था।

अदालत ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध तय करने के लिए यह भी देखा जाना जरूरी है कि आरोपी के कथित शब्दों और व्यवहार के पीछे जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा थी या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला

उच्च न्यायालय ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया। इस फैसले में कहा गया था कि किसी ऐसे व्यक्ति को आरोपी के रूप में मुकदमे में शामिल करने की शक्ति असाधारण है और इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी और दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को बीच में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने के लिए केवल आरोप तय करने के स्तर के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर्याप्त नहीं होते। इसके लिए ज्यादा मजबूत और ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

क्या है पूरा मामला?

मामला बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है, जहां दुष्कर्म और धमकी के आरोपों में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मुख्य आरोपी हिम्मत सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। जबकि उसके पिता वेगराज सिंह और बड़े भाई दौलत सिंह को जांच के दौरान आरोपों से बाहर रखा गया था। हालांकि, मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया कि वेगराज सिंह और दौलत सिंह ने उसके लिए चमार शब्द का इस्तेमाल किया था। इस बयान के बाद ट्रायल कोर्ट ने दोनों को मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी कर दिया।इसके खिलाफ दोनों आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया।

पहले के बयानों में नहीं था आरोपियों का जिक्र

अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि जातिसूचक टिप्पणी से जुड़े पीड़िता के पहले के बयानों में उनके खिलाफ किसी विशेष भूमिका या कृत्य का उल्लेख नहीं किया गया था। पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज बयानों में भी अपीलकर्ताओं पर ऐसा कोई स्पष्ट आरोप नहीं था। अदालत ने कहा कि विचारण अदालत ने अपीलकर्ताओं की मिलीभगत की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करने वाली किसी विश्वसनीय और ठोस सामग्री या साक्ष्य न होने के बावजूद बीएनएसएस की धारा 358 के तहत उन्हें समन जारी करने में जल्दबाजी की और इस तरह कानूनी भूल की।

सीएचसी अधीक्षक का दवा बाहर की दवा लिखते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सुल्तानपुर। अखंडनगर सीएचसी पर हुए अधीक्षक पर हुए हमले मामले में नया मोड़ आ गया है।जेल गए युवक के भाई ने अधीक्षक पर बाहर की दवा लिखने के आरोप में हुए विवाद में जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए उसके भाई को जेल भेजवाने का आरोप लगाया है। साथ ही अधीक्षक का पर्ची पर बाहर की दवा लिखते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दे कि बुधवार को अखंड नगर थाना क्षेत्र के प्राणनाथपुर बछेड़यिा गांव निवासी सचिन गौड़ पुत्र विनोद गौड़ को अखननगर पुलिस ने सीएचसी अधीक्षक डॉ सतेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में जेल भेज दिया था।मामले में जेल गए सचिन गौड़ के भाई आकाश गौड़ का आरोप है कि बुधवार को उसे बुखार था वह भाई सचिन के साथ दिखाने सीएचसी गया था।सीएचसी में अधीक्षक द्वारा बाहर की दवा लिखी गई जब उसके भाई सचिन ने चिकित्सक से अंदर की दवा देने को कहा तो चिकित्सक भड़क गए।

स्कूली बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए डायरिया के प्रति किया जागरूक

आर्यावर्त संवाददाता

फ़िरोज़ाबाद। डायरिया के प्रति जागरूकता की अलख जगाने के उद्देश्य से जिले के स्कूलों में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।1 इसी क्रम में शुक्रवार को शिक्षा विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू (KENVUE) के सहयोग से "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के तहत नारखी ब्लॉक के कपवाली गाँव स्थित कंपोजिट विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी।1 प्रतियोगिता में कक्षा-आठ तक के 15 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें अंकुश पहले, निशांक दूसरे और बुलबुल तीसरे स्थान पर रहीं।1 प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य बच्चों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर आयोजित गोष्ठी में बच्चों को

डायरिया के कारण, बचाव और उपचार आदि के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज शर्मा ने कहा कि इस प्रतियोगिता और गोष्ठी के माध्यम से बहुत ही सहज और सरल तरीके से बच्चों के बीच डायरिया के संभावित कारणों एवं बचाव की समझ विकसित करने की कोशिश की गयी, जो कि बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगी।1 उन्होंने कहा कि अभी बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियों से बचाव का सबसे सरल और कारगर तरीका साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह से धुलना है। खाना खाने और खाना बनाने से पहले, शौच के बाद एवं घर की साफ सफ़ाई के बाद हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह धुलते हैं तो हाथ स्वच्छ एवं कीटाणु मुक्त होंगे और बीमारियां दूर रहेंगी। पीएसआई इंडिया के राजेश कुमार प्रजापति ने हाथ धोने के प्रमुख छह चरणों के बारे में बताया और कहा कि इनका पालन कर बच्चों को डायरिया समेत कई अन्य संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित बनाया जा सकता है। बच्चे को दस्त की शिकायत हो तो तुरन्त ओआरएस का घोल एवं जिंक देना शुरू करना चाहिए जो कि स्थानीय सरकारी अस्पतालों एवं आशा, एएनएम दीदी के पास निःशुल्क उपलब्ध है।

कार्यक्रम में सहायक अध्यापक रजनीगंधा, मिथिलेश, ममता, पीएसआई इंडिया से कैफुल हसन आदि उपस्थित रहे। इसी क्रम में गत दिनों कंपोजिट विद्यालय सैलाई और पीएमश्री स्कूल कोटला में भी पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों को डायरिया के प्रति जागरूक किया गया।

यूपी में दर्दनाक हादसा : कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, दो की मौत और कई गंभीर घायल

आर्यावर्त संवाददाता

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के जैतीपुर थाना क्षेत्र के बमिहाना गांव से कांवड़ लेने गए 15 कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्राली में शुक्रवार सुबह नवादा मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक से पीछे से टक्कर लग गई। हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बमिहाना गांव से 15 कांवड़ियों का जत्था गुरुवार की रात करीब 12 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली से बदायूं के दातागंज के डांडी घाट के लिए रवाना हुआ था। वहां से रामगंगा नदी से जल लेकर शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे सभी अपने गांव के शिव मंदिर के लिए लौट रहे थे। नवादा मोड़ पुलिस चौकी से करीब 500 मीटर पहले दातागंज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर लग गई। ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क किनारे लगे बिजली के पोल को तोड़ते हुए खाई में पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बैठे कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए। आगे कांवड़ लेकर चल रहे शिवम मिश्रा समेत कुछ अन्य साथी भी ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गए।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा। कुछ घायलों को बरेली ले जाया गया, जहां बमिहाना निवासी अमन (20) और गुड्डू (30) को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का जैतीपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि राजकीय मेडिकल कॉलेज, शाहजहांपुर रेफर किया गया है। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि ट्रक चालक पुलिस हिरासत में है। उसका सीएचसी में इलाज चल रहा है। तहरीर के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आईपीएस अधिकारी बने विनीत जायसवाल, अब सुल्तानपुर की कमान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश कैडर के 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी विनीत जायसवाल को प्रदेश में हुए बड़े पुलिस फेरबदल के तहत सुल्तानपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इससे पहले वह गोंडा के एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 21 अगस्त 2026 को हुए तबादलों में गोंडा की कमान बिजनौर के एसपी अभिषेक को सौंपी गई है।

विनीत जायसवाल का जन्म 1 जुलाई 1988 को हुआ और उनका गृह स्थान गोरखपुर दर्ज है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने निजी क्षेत्र की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया। इसके बाद सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर यूपीएससी की तैयारी शुरू की और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। विनीत जायसवाल के पिता राधेश्याम जायसवाल जेल अधीक्षक रह चुके हैं। बताया जाता है कि प्रशासनिक सेवा के माहौल का उनके करियर पर प्रभाव पड़ा। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध नगर, शामली और हाथरस समेत कई स्थानों पर जिम्मेदारियां संभालीं। नोएडा में उनके कार्यकाल के दौरान होमगार्ड वेतन घोटाले और बाइक बोट प्रकरण जैसे चर्चित मामलों की जांच भी सामने रही। विनीत जायसवाल 16 दिसंबर 2023 से गोंडा के एसपी थे। उनके कार्यकाल में साइबर अपराध की रोकथाम, अपराध नियंत्रण और जनसुनवाई पर जोर दिया गया। गोंडा पुलिस ने उनके निर्देशन में 'ऑपरेशन साइबर कवच' जैसे जागरूकता अभियान भी चलाए। अब सुल्तानपुर में उनकी नई जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आईपीएस अफसर की मां की हत्या का मामला : 6 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस, करीबियों पर घूमी जांच

आर्यावर्त संवाददाता

अंबेडकरनगर। आइपीएस आशुतोष मिश्र की मां की हत्या और लूट के मामले में घटना के छह दिन बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। पुलिस की जांच अब घटना से जुड़े करीबियों के इर्द-गिर्द भी घूम रही है। हालांकि, अभी तक किसी के विरुद्ध कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। मालीपुर के धवरुवा मजरे रूढ़ा निवासी आइपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्र की मां इंद्रा देवी का शव रविवार की सुबह उनके घर में मिला था। मामले में हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने जांच के लिए पांच टीमें गठित की हैं, जो अलग-अलग बिंदुओं पर साक्ष्य जुटा रही हैं।

पुलिस घटना के पीछे की वजह, घर में आने-जाने वाले लोगों और आसपास की गतिविधियों के साथ ही अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है। पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी जोन प्रवीण कुमार स्वयं प्रतिदिन जांच की प्रगति की रिपोर्ट ले रहे हैं। छह दिन बीतने के बाद भी हत्या और लूट की इस घटना का राज नहीं खुल सका है। ऐसे में पुलिस के सामने आरोपितों तक पहुंचने के साथ ही वारदात के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने की चुनौती बनी हुई है। क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार सिंह ने कहा कि जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

शिक्षकों-कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा

सुल्तानपुर। पुरानी पेंशन बहाली और सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता के विरोध में अटेवा सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह गौरा के नेतृत्व में शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिकोनिया पार्क से शुरू हुई यात्रा डाकखाना, जिला अस्पताल व आजाद पार्क होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया।

यात्रा में सैकड़ों शिक्षकों-कर्मचारियों के साथ विभिन्न विभागों एवं शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने सहभागिता की। हाथों में तिरंगा लेकर प्रतिभागियों ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा अधिकार है। सेवारत शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता को लेकर भी वक्ताओं ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के हितों और सेवा-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को न्यायपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।

अनफिट स्कूली वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का अभियान, नौ वाहन निरुद्ध

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। बच्चों के सुरक्षित परिवहन को लेकर चलाए जा रहे 'मिशन सेफ फ्यूचर 2.0' के तहत शुक्रवार को जिले में अनफिट एवं अनाधिकृत रूप से संचालित स्कूली वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने व्यापक अभियान चलाया। कार्रवाई में नौ वाहनों को निरुद्ध किया गया, जबकि चार अन्य वाहनों का चालान किया गया।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 11 से 25 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), अयोध्या संजय कुमार झा के नेतृत्व में जिले में कार्रवाई की गई। इस दौरान यश कान्वेंट स्कूल, शेम्फोर्ड इंटरनेशनल स्कूल और स्टेला मॉरिस कान्वेंट स्कूल का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अनाधिकृत रूप से संचालित नौ स्कूली वाहनों को निरुद्ध करने के साथ चार अन्य वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी ने एआरटीओ कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को दोनों प्रवर्तन टीमों की ब्लॉकवार ड्यूटी लगाकर अनफिट और बिना परमिट संचालित स्कूली वाहनों के खिलाफ नियमित रूप से चालान एवं निरुद्ध करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।कार्रवाई के दौरान एआरटीओ (प्रशासन) अलका शुक्ला, एआरटीओ (प्रवर्तन) भूपेश कुमार गुप्ता, यात्री कर अधिकारी शैलेन्द्र तिवारी, संभागीय निरीक्षक पंकज तथा प्रवर्तन दल के राघवेंद्र, ओमप्रकाश और अफजाल मौजूद रहे।विभाग की ओर से बताया गया कि 25 अगस्त को एआरटीओ कार्यालय में स्कूली वाहन चालकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण का आयोजन किया जाएगा।

यूपीसीडा की नई पहल, बंद औद्योगिक इकाइयों के भूखंड वापस खरीदेगा प्राधिकरण

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। लंबे समय से बंद पड़ी और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के भूखंडों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने कवायद तेज कर दी है। प्राधिकरण ने गोरखपुर-बस्ती मंडल और मऊ के 229 ऐसे आवंटियों को नोटिस भेजा है, जिनके भूखंड पर अभी तक औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हो सकी है या स्थापित इकाई लंबे समय से बंद है। बस्ती में सबसे अधिक 55 उद्यमियों को नोटिस दिया गया है।

यूपीसीडा की नई पहल के तहत ऐसे आवंटियों को भूखंड के लिए खरीदार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। यदि उद्यमी बंद या बीमार इकाई को दोबारा संचालित करने की स्थिति में नहीं हैं तो यूपीसीडा प्रचलित बाजार दर के 90 प्रतिशत मूल्य पर भूखंड वापस खरीदने को तैयार है। इससे वर्षों से बंद इकाइयों में फंसी उद्यमियों की पूंजी वापस मिलने का रास्ता साफ होगा।

दरअसल, लखनऊ में हुई यूपीसीडा की बोर्ड बैठक में बंद और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के भूखंड स्वयं वापस लेने का निर्णय किया गया था। इसी के क्रम में क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे भूखंडों की पहचान कर आवंटियों को नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस में इकाई के बंद या बीमार होने का कारण और वर्तमान स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है।

यूपीसीडा अधिकारियों के अनुसार, नोटिस का जवाब मिलने के बाद प्रत्येक मामले की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद भूखंड वापस लेने या अन्य कार्रवाई के संबंध में मुख्यालय से दिशा-निर्देश मांगे जाएंगे।

> बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में 229 आवंटियों को नोटिस भेजा गया है। आवंटियों से फैक्ट्री के बंद या बीमार होने की वजह की जानकारी मांगी गई है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय से गाइडलाइन मांगी जाएगी।
>
> **-धर्मचंद, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा**

बोरी में शराब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सुल्तानपुर। जिले के करौंदी कला कस्बे में एक दुकान के सामने बोरी में रखी देशी दारू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद भी सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जांच न करके मामले ने लीपापोती की जा रही है।

बता दे कि शुक्रवार को करौंदी कला कस्बे में एक दुकान के सामने बोरी में रखे देशी दारू की पैकेटों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।वीडियो वायरल होने के बाद जब इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए कादीपुर आबकारी इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है।जब आबकारी इंस्पेक्टर कादीपुर बृज राज सिंह से जांच पड़ताल के बारे में पूछा गया तो लीपापोती करते हुए कहा कि अनुज्ञापी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि उसकी दुकान बंद थी।किसने दारू की पैकेट रखी है उसे जानकारी नहीं है।

रामकोट की नित्य परिक्रमा के एक वर्ष पूरे होने पर उमड़ा रामभक्तों का ज्वार, अयोध्या में अद्भुत नजारा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र की परिक्रमा से जुड़ी रामकोट की नित्य परिक्रमा के एक वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को इसका भव्य और वृहद स्वरूप देखने को मिला।

वर्षगांठ के अवसर पर हजारों रामभक्तों और संत-महात्माओं ने राम नाम का जयघोष करते हुए सवा कोसी परिक्रमा की। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर समेत रामकोट क्षेत्र के 108 प्रमुख मंदिरों को समाहित करते हुए करीब चार किलोमीटर की यह परिक्रमा 21 अगस्त 2025 से नियमित रूप से शुरू हुई थी। बीते एक वर्ष से संत और रामभक्त प्रतिदिन सुबह रामकोट की नित्य परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा एक घंटे से कम समय में पूरी हो जाती है।

वर्षगांठ पर ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा की अगुवाई में आयोजित परिक्रमा में बड़ी संख्या में संत शामिल हुए। राम नाम के

जयघोष के बीच श्रद्धालुओं ने रामजन्मभूमि के चारों ओर स्थित मंदिरों की परिक्रमा की। इसमें हनुमानगढ़ी समेत रामकोट क्षेत्र के अन्य प्रमुख मंदिर भी शामिल हैं।

रामकोट की नित्य परिक्रमा की परंपरा रामजन्मभूमि क्षेत्र के मंदिरों की परिक्रमा से जुड़ी रही है। वर्षगांठ के आयोजन में इसे व्यापक स्वरूप दिए जाने से रामभक्तों में उत्साह दिखाई दिया।

डॉ. अनिल मिश्रा ने कहा कि रामकोट की नित्य परिक्रमा किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं, बल्कि रामभक्तों की आस्था और धार्मिक परंपरा से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से नियमित रूप से चल रही इस परिक्रमा में संतों और श्रद्धालुओं की सहभागिता लगातार बनी हुई है।

भारत-जापान की युवा पीढ़ी के संवाद से मजबूत होगी दोस्ती, मुख्यमंत्री ने कहा- विद्यार्थी बनेंगे दोनों देशों के भविष्य के राजदूत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश-जापान निवेश बैठक-2026 के क्रम में आयोजित विशेष कार्यक्रम 'ए डायलॉग विद द फ्यूचर' में भारत और जापान के विद्यार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री और जापान के यामानाशी प्रान्त के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में यामानाशी से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान किया।मुख्यमंत्री ने जापानी विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों तथा लखनऊ के विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत जापानी अभिवादन 'ओहायो गोजाइमासु' से की। उन्होंने कहा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र है और इसे भारत का हृदयस्थल भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस अवध क्षेत्र में यह संवाद हो रहा है, उसी क्षेत्र में अयोध्या स्थित है, जो भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है।मुख्यमंत्री ने जापानी विद्यार्थियों की उत्तर प्रदेश यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने आगरा में ताजमहल देखा है। मथुरा, भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि, भी उनके निकट है। अब उन्हें वाराणसी और सारनाथ जाने का अवसर मिलेगा। सारनाथ वह पवित्र स्थल है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। वाराणसी विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इस प्रकार जापान से आए विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिकता, संस्कृति और सभ्यतागत विरासत को करीब से समझने का अवसर भी है।योगी ने कहा कि यह केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, दो परम्पराओं और दो देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में दोनों देशों के विद्यार्थी भविष्य के राजदूत की भूमिका निभा सकते हैं और भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं।उन्होंने कहा कि एक ओर भारत की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, तो दूसरी ओर तकनीक, परम्परा, अनुशासन और प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले जापान के विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी लखनऊ के किसी गांव से आया है तो दूसरा जापान के किसी गांव से, एक हिंदी बोलता है तो दूसरा जापानी, लेकिन दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि वे अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी विद्यार्थियों के लिए यह संवाद भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुम्बकम्, भारतीय भाषाओं, दर्शन, पर्व-त्योहारों और उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर है। जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में जाने, यही इस संवाद की बड़ी उपलब्धि होगी।उन्होंने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए भी यह जापान की कार्य संस्कृति, जीवन-दर्शन, अनुशासन, 'इकीगाई', टीम भावना, पारस्परिक सम्मान, स्वच्छता, समयबद्धता, पारम्परिक कलाओं और उत्सवों को समझने का अवसर है। विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि दोनों देश एक-दूसरे से सीखें और अपनी श्रेष्ठ परम्पराओं तथा विचारों को साझा करें।मुख्यमंत्री ने भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और जापान के सामाजिक सामंजस्य की भावना के बीच समानता को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है। उन्होंने कहा कि संकीर्ण सोच वाले लोग अपना और पराया देखते हैं, जबकि उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। इसी भावना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के संकल्प में भी देखा जा सकता है।योगी ने कहा कि जापान की शक्ति आत्मअनुशासन, परिशुद्धता, गुणवत्ता, टीम भावना और नवाचार में है, जबकि भारत की शक्ति युवा शक्ति, प्रतिभा, विविधता, सृजनात्मकता और सबको साथ लेकर चलने की भावना में है। जब भारत और जापान की इन शक्तियों का मेल होगा तो इसका लाभ केवल दोनों देशों के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज वे विद्यार्थी हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में इन्हीं में से वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, कलाकार, खेल चैंपियन, नीति निर्माता और वैश्विक नेतृत्वकर्ता निकलेंगे। इसलिए उन्हें एक-दूसरे की भाषा सीखने के साथ-साथ एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। एक-दूसरे की संस्कृति, मूल्यों और जीवन-दृष्टि का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत रिश्ते कक्षाओं, परिसरों, प्रयोगशालाओं और युवा मस्तिष्कों के बीच बनते हैं। आज के यही बच्चे कल भारत-जापान साझेदारी के सबसे प्रभावशाली राजदूत होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन का समापन जापानी भाषा में 'अरिगातो गोजाइमासु' कहकर किया।यामानाशी प्रान्त के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों देशों के विद्यार्थियों को संवाद का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। उन्होंने लखनऊ के विद्यार्थियों का भी विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने जापानी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत किया।गवर्नर ने कहा कि दोनों देशों को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि दोनों देशों में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं। उन्होंने भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और यामानाशी की उस सोच का उल्लेख किया, जिसमें एक-दूसरे के लोगों को समृद्ध बनाने के साथ अपनी समृद्धि सुनिश्चित करने की भावना निहित है।

जापानी निवेशक उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया आह्वान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी द्वारा आयोजित जापान-भारत व्यापार नेटवर्किंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जापानी निवेशकों से उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जापान की उन्नत तकनीक, गुणवत्ता और विशेषज्ञता तथा उत्तर प्रदेश के विशाल कृषि आधार, प्रतिभाशाली मानव संसाधन और विविध कृषि उत्पादों का समन्वय प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और जापान के बीच भगवान बुद्ध की करुणा, शांति, मानव कल्याण और ज्ञान की शिक्षाओं से जुड़ा सदियों पुराना आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध है। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध से जुड़ी पवित्र स्मृतियों और जापान की समृद्ध बौद्ध परंपराओं के बीच दोनों देशों की साझा विरासत और आत्मीयता का मजबूत सेतु मौजूद है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत-जापान के रणनीतिक और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर जापान का दौरा किया और वहां के निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसी का परिणाम है कि लखनऊ में जापान और उत्तर प्रदेश के उद्यमी एवं निवेशक एक मंच पर बैठकर व्यापारिक संभावनाओं और भविष्य की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और प्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख सूचीबद्ध किसान हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को ऐसे उत्पादों और फसलों के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिनसे उन्हें उनकी मेहनत और उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य पर खरीदकर उन्हें मूल्यवर्धित उत्पादों में बदल सकते हैं और देश-दुनिया के बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

संक्षेप

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दो युवक गिरफ्तार, गुडम्बा पुलिस ने कुकरैल जंगल से दबोचा

लखनऊ। गुडम्बा थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी से कथित रूप से जबरन शारीरिक संबंध बनाने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर कुकरैल जंगल पिकनिक स्पॉट पुलिया के पास से पकड़ा।पुलिस के अनुसार 20 अगस्त 2026 को पीड़िता के परिजन की ओर से गुडम्बा थाने में लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 330/2026, धारा 65(1), 123 और 351(3) बीएनएस तथा धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर में नामजद आरोपियों पर नाबालिग पुत्री के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था।मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर तलाश शुरू की। 21 अगस्त को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कुकरैल जंगल पिकनिक स्पॉट पुलिया के पास घेराबंदी की और दोनों वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अदनान अंसारी पुत्र मो. इजहार, निवासी मेहंदी टोला, थाना अलीगंज, लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष और हिशाम अंसारी उर्फ शावेज पुत्र मुनीर अहमद अंसारी, निवासी मेहंदी टोला, थाना अलीगंज, लखनऊ, उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार पूछताछ में हिशाम अंसारी उर्फ शावेज ने बताया कि वह एसी सर्विसिंग का काम करता है और पीड़िता से इंस्टाग्राम के माध्यम से करीब आठ महीने से परिचित होने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के मुताबिक आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अपना पक्ष रखा जाएगा। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच कर रही है।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार मिश्र, अतिरिक्त निरीक्षक भानु प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक दिवाकर सरोज, हेड कांस्टेबल पारस नाथ वर्मा और कांस्टेबल विजय नरेश शामिल रहे।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि परिवहन विभाग के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए निर्धारित मद से खर्च की जाएगी।सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य प्रदेश में ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहित करना, वायु प्रदूषण में कमी लाना और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को कम करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलने से नागरिकों को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।शासन ने स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित वित्तीय नियमों और योजना की गाइडलाइन के अनुरूप करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही धनराशि का आहरण केवल आवश्यकता के अनुसार किए जाने को कहा गया है। संबंधित विभाग को योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और स्वीकृत धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार के इस फैसले से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 50 करोड़ रुपये की यह स्वीकृति हरित परिवहन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे प्रदूषण नियंत्रण के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

एकता सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक का पदभार संभाला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निदेशक पद पर एकता सिंह ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वह सर्व शिक्षा अभियान में अपर राज्य परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत थीं और वर्ष 2024-25 तक इस दायित्व का निर्वहन किया।प्रशासनिक और विभागीय कार्यों का अनुभव रखने वाली एकता सिंह के पंचायती राज निदेशालय में मिशन निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को और गति मिलने की उम्मीद है।पंचायती राज विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को सशक्त बनाने, ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निदेशक के रूप में एकता सिंह की जिम्मेदारी ग्रामीण स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू कराने में महत्वपूर्ण होगी।विभागीय अधिकारियों के अनुसार नई जिम्मेदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, साफ-सफाई, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा।

ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास टावर पर चढ़ी महिला, पुलिस की समझाइश के बाद सकुशल उतारी गई

लखनऊ। बाजारखाला थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक टावर पर एक महिला चढ़ गई। सूचना मिलते ही बाजारखाला थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग की टीम को भी तत्काल बुलाया गया।पुलिस के अनुसार महिला गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र की निवासी है। मौके पर मौजूद लोगों से प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि महिला का अपने पड़ोसी से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है।घटना की जानकारी मिलते ही महिला के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने महिला से लगातार बातचीत कर उसे समझाने-बुझाने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद महिला पुलिस की बात मान गई और उसे सकुशल टावर से नीचे उतार लिया गया।पुलिस के मुताबिक महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घटना के दौरान पुलिस और दमकल विभाग की तत्परता से महिला को सकुशल नीचे उतार लिया गया।

उत्तर प्रदेश में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादला सूची में पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अधिकारियों को वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए विभिन्न जिलों में तैनाती दी गई है।तबादला सूची के अनुसार विनीत जायसवाल, आईपीएस-आरआर-2014 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पद से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर बनाया गया है।चारू निगम, आईपीएस-आरआर-2014 को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक यू0पी0-112, लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है।अविनाश पाण्डेय, आईपीएस-आरआर-2015 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के पद से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ भेजा गया है।

बी.जी.टी.एस. मूर्ति, आईपीएस-आरआर-2015 को पुलिस अधीक्षक यू0पी0-112, लखनऊ से स्थानांतरित कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के पद पर तैनाती दी गई है।अभिषेक, आईपीएस-आरआर-2015 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर के पद से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक गोण्डा बनाया गया है।विकास कुमार, आईपीएस-आरआर-2017 को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के पद से स्थानांतरित कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के पद पर तैनाती दी गई है।कृष्ण कुमार, आईपीएस-आरआर-2018 को पुलिस अधीक्षक सम्भल के पद से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक बिजनौर के पद पर भेजा गया है।विकास चन्द्र त्रिपाठी, आईपीएस-एसपीएस-0 को पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक के पद से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक सम्भल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बलरामपुर जिला सहकारी बैंक के गठन को मंजूरी, बलरामपुर और गोंडा के किसानों को मिलेंगी स्थानीय बैंकिंग सुविधाएं

लखनऊ, (आरएनएस)। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से अधिसूचना जारी कर बैंक के गठन की अनुमति प्रदान करते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैंक के गठन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 14.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।प्रस्तावित बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का कार्यक्षेत्र बलरामपुर और गोंडा जनपद होगा। जिला सहकारी बैंक के गठन से दोनों जिलों में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों, सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्र के खाताधारकों को स्थानीय स्तर पर

बीबीएयू की नई वेबसाइट आधुनिक डिजिटल तकनीक और केंद्रीकृत डेटाबेस से होगी लैस, जल्द होगी लॉन्च

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) की नई वेबसाइट को आधुनिक डिजिटल तकनीक और केंद्रीकृत डेटाबेस प्रणाली के साथ विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में कम्प्यूटर साइंस विभाग ने इसे पूरी तरह इन-हाउस तैयार किया है। नई वेबसाइट शीघ्र ही लॉन्च की जाएगी। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, शोध और प्रशासनिक सूचनाओं को अधिक व्यवस्थित, सुलभ, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाना है।नई वेबसाइट को आधुनिक बैकएंड प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय के शिक्षक और विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय अपने-अपने स्तर पर संबंधित सूचनाओं को स्वयं अपडेट और प्रबंधित कर सकेंगे। प्रत्येक शिक्षक को एक विशिष्ट लॉगिन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपनी शैक्षणिक प्रोफाइल, शोध प्रकाशन, परियोजनाएं, पेटेंट, उपलब्धियां और अन्य व्यावसायिक जानकारी स्वयं अपडेट कर सकेंगे। शिक्षक द्वारा किए गए बदलाव उनकी व्यक्तिगत प्रोफाइल के साथ-साथ संबंधित विभाग के पेज पर भी तत्काल प्रदर्शित होंगे।कम्प्यूटर साइंस विभाग के प्रो. संजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि नई वेबसाइट को पूरी तरह विश्वविद्यालय के स्तर पर विकसित किया गया है। इसके डिजाइन, तकनीकी संरचना और विभिन्न सुविधाओं के विकास का कार्य विश्वविद्यालय की अपनी टीम ने किया है। इससे वेबसाइट के संचालन और भविष्य में आवश्यक बदलावों के लिए बाहरी निर्भरता कम होगी।नई व्यवस्था के तहत विभागाध्यक्षों, डीन, निदेशकों, परीक्षा नियंत्रक, प्रॉक्टर, कुलसचिव, अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों को अलग-अलग लॉगिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके माध्यम से संबंधित विभागों, स्कूलों, केंद्रों और प्रशासनिक अनुभागों की सूचनाओं को प्रबंधित एवं अपडेट किया जा सकेगा।केंद्रीकृत डेटाबेस प्रणाली की मदद से विभागीय और संस्थागत सूचनाएं वेबसाइट के विभिन्न हिस्सों में स्वतः व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित होंगी। इससे सूचनाओं को बार-बार अलग-अलग स्थानों पर अपडेट करने की आवश्यकता कम होगी और विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों तथा अन्य हितधारकों को एक ही स्थान से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।नई वेबसाइट पर शैक्षणिक और प्रशासनिक सूचनाओं को कुछ ही क्लिक में खोजने, फिल्टर करने और प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

घाघरा नदी के बदलते बहाव से लेकर बुंदेलखंड की भू-आकृतियों तक

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बदलती जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं और तेजी से बदलते भू-उपयोग के दौर में किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक परिस्थितियों की सटीक जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। नदियों के बदलते प्रवाह, भू-आकृतियों, जल निकासी, भूजल संभावनाओं और भूमि की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन भविष्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक मानचित्रण और अध्ययन करा रहा है।विभाग के अंतर्गत कार्यरत रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, उत्तर प्रदेश (आरसैक-यूपी) द्वारा घाघरा नदी की भू-आकृतिक गतिशीलता का व्यापक अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर और जालौन जनपदों में जियोमॉर्फोलॉजी एवं लिनियामेंट मैपिंग का कार्य कराया जा रहा है। इन परियोजनाओं में उपग्रह आंकड़ों, भू-स्थानिक सूचना प्रणाली, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।घाघरा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में शामिल है और इसका प्रवाह मार्ग तथा स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। नदी के बहाव में परिवर्तन, तटों का कटाव, जल निकासी और बाढ़ की स्थिति आसपास के जनजीवन तथा कृषि भूमि को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में नदी के वर्तमान व्यवहार के साथ भविष्य में होने वाले संभावित परिवर्तनों को समझना प्रभावी नदी प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण के लिए आवश्यक है।इसी उद्देश्य से आरसैक-यूपी द्वारा बहराइच से बलिया तक फैले घाघरा नदी उप-बेसिन का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। परियोजना के तहत जल निकासी, भू-आकृति विज्ञान, ढाल, वर्षाजल अपवाह, प्राचीन जल निकासी तंत्र और भूमि उपयोग से जुड़े विभिन्न भू-स्थानिक आंकड़ों का एकीकृत अध्ययन किया गया है। इससे नदी और उसके आसपास के भू-भाग के बीच संबंधों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिल रही है।आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वेक्टर आंकड़ों को रास्टर प्रारूप में परिवर्तित कर उनका गुणवत्ता परीक्षण और पुनः एकीकरण किया गया। इसके अलावा वर्ष 2025 में मानसून से पहले और मानसून के बाद क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर उपग्रह से प्राप्त जानकारी का जमीनी स्तर पर सत्यापन किया गया घाघरा के बदलते स्वरूप को समझने के लिए केवल वर्तमान स्थिति का अध्ययन नहीं किया गया, बल्कि वर्ष 1975 के सर्वे ऑफ इंडिया के स्थलाकृतिक मानचित्रों के साथ विभिन्न वर्षों के मानसून पूर्व और मानसून बाद के उपग्रह चित्रों का भी इस्तेमाल किया गया। इन आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से नदी के बहाव क्षेत्र में समय के साथ हुए बदलावों की पहचान की गई है।अध्ययन को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए नदी क्षेत्र को छह उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में नदी के बहाव, भू-आकृतिक बदलाव और उससे संबंधित परिस्थितियों का अलग-अलग विश्लेषण किया गया।

शराब ठेके पर विवाद के बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या, दो गिरफ्तार और दो बाल अपचारी संरक्षण में

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। महिगवां थाना क्षेत्र में शराब के ठेके पर हुए विवाद के बाद एक युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त थार कार और लकड़ी का फट्टा बरामद किया है। मामले में चार मोबाइल फोन और 36,700 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार ग्राम अटेसुआ, थाना इटौंजा निवासी सोनू सिंह ने 19 अगस्त को महिगवां थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई मोनू उर्फ दिलीप सिंह के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर महिगवां थाने में मुकदमा संख्या 126/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत

मामला दर्ज किया गया।घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश और सुरागरसी कर रही थी। इसी दौरान 20 अगस्त को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल चार व्यक्ति अतरौरा जाने वाले मार्ग पर पुराने भट्ठे से आगे गांव के पूर्व स्थित मंदिर के चबूतरे पर बैठे हैं और वहां से भागने की फिराक में हैं।सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही चारों आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया।पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 19 अगस्त की शाम शाहपुर स्थित देशी शराब के ठेके पर मोनू उर्फ दिलीप सिंह और सचिन यादव के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद सचिन यादव ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुलाया। पुलिस के अनुसार कुछ देर बाद अभिषेक यादव उर्फ शेखर, अनुज सिंह, कुलदीप उर्फ टेढ़े और दो बाल अपचारी वहां पहुंचे।पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंचने के बाद सभी ने मिलकर मोनू उर्फ दिलीप सिंह के साथ लात-घूंसों और डंडे से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल होकर मोनू जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में उन्हें जानकारी हुई कि मारपीट में घायल मोनू की मौत हो गई है। इसके बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की योजना बना रहे थे।पुलिस ने घटना में संलिप्तता के पर्याप्त आधार मिलने पर अभिषेक यादव उर्फ शेखर और अनुज सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

क्या Gen-Z होना सुरक्षा नियम तोड़ने का लाइसेंस है?

सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पर्यटक भारतीय सेना के जवानों के साथ बहस कर रही है और खुद को "Gen-Z" बताकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। शायद इस महिला को पता नहीं कि सीमा पर खड़े सैनिक की ड्यूटी कोई पर्यटन सेवा नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे किसी पर्यटक की सुविधा, बहस या अधिकारों के नाम पर दरकिनार कर दिया जाए। साथ ही वीडियो में महिला खुद को "Gen-Z" बताते हुए यह कहती सुनाई देती है कि वह "यह बकवास बर्दाश्त नहीं करेगी।" यहां सवाल यह उठता है कि क्या किसी पीढ़ी का टैग राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल से ऊपर हो सकता है?

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिखी घटना कारगिल सेक्टर के एक संवेदनशील हाई-एल्टीट्यूड चेक पोस्ट की है, जहां पर्यटकों के एक समूह को प्रतिबंधित दिशा में आगे बढ़ने से रोका गया। बताया जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक अनुमति और सुरक्षा नियम लागू थे। एक अन्य विवरण में इसे मिनामार्ग या मिनीमार्ग चेक पोस्ट के पास अस्थायी सड़क प्रतिबंध से जुड़ा बताया गया है। वीडियो में दिख रही तस्वीर बेहद स्पष्ट है। एक तरफ शांत रहकर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोशिश करता जवान और दूसरी तरफ अपनी यात्रा, दूरी और अधिकारों का हवाला देकर बहस करता पर्यटक समूह।

महिला पर्यटक का यह तर्क कि "हम Gen-Z हैं, हम यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे", दरअसल उस मानसिकता को उजागर करता है जिसमें व्यक्तिगत सुविधा को व्यवस्था और सुरक्षा से ऊपर मान लिया जाता है। Gen-Z होना न कोई विशेष सुरक्षा पास है, न ही यह कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल को चुनौती देने का लाइसेंस है। सेना यह नहीं देखती कि सामने खड़ा व्यक्ति किस पीढ़ी का है; उसे यह देखना होता है कि सीमा सुरक्षित रहे, कोई संदिग्ध गतिविधि न हो और कोई नागरिक अनजाने में किसी खतरे की जद में न पहुंच जाए।

देखा जाये तो कारगिल और नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाके सामान्य पर्यटन स्थल नहीं हैं। यह वही संवेदनशील भूभाग है जहां भारत ने युद्ध का सामना किया है, जहां घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों का इतिहास रहा है और जहां मौसम, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां तथा सैन्य गतिविधियां हर समय सुरक्षा की अलग चुनौतियां पैदा करती हैं। ऐसे में सड़क बंद होना, आवाजाही नियंत्रित होना, चेकिंग होना या किसी क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति मांगना कोई "एंटी-टूरिस्ट" रवैया नहीं, बल्कि एक जरूरी सुरक्षा व्यवस्था है।

सेना और सुरक्षा एजेंसियों को वहां इसलिए तैनात रहना पड़ता है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में खतरे केवल दिखाई देने वाले नहीं होते। कई बार खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी या घेराबंदी की जरूरत पड़ सकती है। कभी सैन्य काफिले की आवाजाही होती है, कभी खराब मौसम या भूस्खलन के कारण रास्ता असुरक्षित हो जाता है और कभी किसी संभावित खतरे को देखते हुए नागरिकों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी जाती है। ऐसे निर्णय किसी एक पर्यटक को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि दर्जनों या सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए लिए जाते हैं।

बर्फीली चोटियों, दुर्गम सड़कों और हर वक्त मौजूद संभावित खतरे के बीच जवान इसलिए तैनात है ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहें और पर्यटन जैसी सामान्य गतिविधियां भी संभव हो सकें। ऐसे में किसी पर्यटक का जवानों से यह पूछना कि रास्ता आखिर क्यों बंद किया गया है, हर परिस्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास मौजूद खुफिया जानकारी, किसी विशेष इनपुट या चल रहे ऑपरेशन का कारण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कई बार एक मामूली-सा खुलासा भी सुरक्षा अभियान और जवानों की जान को जोखिम में डाल सकता है। देश पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए आतंकी हमले की भयावहता देख चुका है और पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले की त्रासदी भी झेल चुका है। ऐसे अनुभव साफ बताते हैं कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को लेकर एक छोटी-सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए पर्यटकों को यह समझना होगा कि जब सेना या सुरक्षा बल किसी रास्ते को बंद करते हैं या आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो हर निर्णय के पीछे की वजह कैमरे के सामने बताना संभव नहीं होता। ऐसे में जवान से बहस करना, वीडियो बनाकर उस पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाना या सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करना केवल असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीरता को न समझ पाने का उदाहरण है। सुरक्षा के मामले में सहयोग और धैर्य ही समझदारी है, क्योंकि कई बार जिस खतरे को आम नागरिक देख नहीं सकता, उसे रोकने के लिए ही जवान वहां खड़ा होता है।

जंगल की लड़ाई शहरों तक पहुंचेगी!

अजीत द्विवेदी

> अब प्रधानमंत्री ने 'दिमागी नक्सल' का एक नया जुमला ईजाद किया है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपने 13वें भाषण में यह जुमला बोला।

पिछले कुछ वर्षों से एक परिघटना के तौर पर 'अर्बन नक्सल की चर्चा हो रही है। बड़े शहरों खास कर महानगरों में रहने वाले कुछ बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार भी किया गया। उनके ऊपर नक्सलियों को समर्थन देने के आरोप लगे। भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के प्रयास के आरोपों में जांच हुई और कई बौद्धिकों के कंप्यूटर से कथित तौर पर हिंसा को समर्थन देने वाले दस्तावेज व चि_यिां बरामद हुईं। इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए फादर स्टेन स्वामी का न्यायिक हिरासत में निधन हो गया। उनके हाथ कांपते थे और उनको पानी पीने के लिए स्ट्रॉ चाहिए था तो उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। सरकार उनके प्रति इतनी सख्त थी कि जेल प्रशासन स्ट्रॉ तक नहीं दे रहा था। गौतम नवलखा से लेकर आनंद तेलतुम्बडे और प्रोफेसर जी साईबाबा तक अनेक लोग गिरफ्तार हुए और लंबे समय तक जेल में रहे।

अब प्रधानमंत्री ने 'दिमागी नक्सल का एक नया जुमला ईजाद किया है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपने 13वें भाषण में यह जुमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जंगल के नक्सलियों, जिनके लिए उन्होंने 'हथियारी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, का सफाया हो चुका है। इसके बाद उन्होंने 'दिमागी नक्सल की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने का आह्वान किया। यह 'अर्बन नक्सल से आगे की परिघटना है। ऐसा लग रहा है कि 'अर्बन नक्सल का विमर्श वांछित परिणाम नहीं दे सका है। शहरी और ग्रामीण विभाजन में यह मामला कहीं खो गया। मध्य वर्ग के कुछ लोगों को एक अवधारणा के तौर पर यह अच्छा लगा लेकिन जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उनमें से ज्यादातर को सामान्य लोग नहीं जानते थे या उनसे कनेक्ट नहीं कर सके। इसलिए उनके लिए ऐसे लोगों को खतरे के तौर पर देखना थोड़ा मुश्किल था। तभी ऐसा लग रहा है कि उससे आगे की परिघटना के तौर पर 'दिमागी नक्सल का विचार प्रस्तुत किया गया है।

प्रधानमंत्री ने इसे अलग से परिभाषित नहीं किया लेकिन जिस तरह उन्होंने 'हथियारी नक्सल के बरक्स 'दिमागी नक्सल को रखा उससे परिभाषा बहुत स्पष्ट है। इसका पहला उद्देश्य तो यह दिख रहा है कि 'अर्बन नक्सल से जो बात ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची उसे 'दिमागी नक्सल के नाम पर पहुंचाया जाए। दूसरा मकसद यह दिख रहा है कि इसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र की बजाय अखिल भारतीय परिघटना बनाया जाए। तीसरा उद्देश्य जंगल की लड़ाई को घर घर में और गली गली में पहुंचाना है। ध्यान रहे लोग नक्सल का एक ही मतलब समझते हैं। जिनको इसका इतिहास, भूगोल भी नहीं पता है वे भी मानते हैं कि नक्सली वो लोग होते हैं, जो सरकार से लड़ते हैं और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करते हैं।

यह बहुत सरलीकृत धारणा है लेकिन आम भारतीय के मन में नक्सली की यही छवि है। यह बात खासतौर से उन इलाकों के लिए कही जा सकती है, जहां नक्सलवाद का असर नहीं रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहां माओवाद या नक्सलवाद का असर रहा उन राज्यों के बाहर इसके बारे में कोई स्पष्ट धारणा लोगों के मन में नहीं है। असर वाले राज्यों में भी शहरी इलाकों में लोग इससे अप्रभावित रहे हैं। तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में इनके प्रति सहानुभूति रखने और इन्हें समर्थन देने वाला भी एक बड़ा तबका हमेशा मौजूद रहा है।

बहरहाल, जो बिल्कुल ही अप्रभावित रहे या नक्सलवाद की परिघटना के भौगोलिक दायरे से बाहर रहे उनके मन में नक्सलियों को लेकर जो धारणा है वह सरकार विरोधी और सुरक्षा बलों पर हमला करने वालों के रूप में है। वे 'दिमागी नक्सल को भी इसी रूप में देखेंगे। उनके लिए 'दिमागी नक्सल वह है, जो सरकार का विरोध कर रहा है। भले विरोध लोकतांत्रिक हो। विरोध के तरीकों के आधार पर फर्क नहीं किया जाएगा। सशस्त्र विरोध और लोकतांत्रिक विरोध एक माने जाएंगे। तभी यह संभव है कि एक बरसात में धंस जाने वाले एक्सप्रेसवे का मुद्दा उठाने वाला 'दिमागी नक्सल मान लिया जाए। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का विरोध वाले से लेकर छात्र आंदोलन का समर्थन करने वालों को भी 'दिमागी नक्सल ठहराया जा सकता है। सरकार की आर्थिक व विदेश नीति पर सवाल उठाने वाला या सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध करने वाला तो निश्चित रूप से 'दिमागी नक्सल माना जाएगा।

भारत या किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करने वालों का बचाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या अगर कोई व्यक्ति मौजूदा व्यवस्था का विरोध करता है, नागरिक सुविधाओं की अनुपस्थिति की ओर ध्यान दिलाता है, सरकार से लेकर देश की अन्य संस्थाओं की साख पर सवाल उठाता है और उन्हें विश्वसनीय नहीं मानता है, उन्हें बदलने की बात करता है तो उसे 'दिमागी नक्सल कहा जा सकता है? ध्यान रहे ऐसे ही लोगों को 'अर्बन नक्सल कहा गया था। देश के बौद्धिकों को 'अर्बन नक्सल कहा गया। किसान आंदोलन करने वालों को खालिस्तानी और उस आंदोलन का समर्थन करने वालों को 'अर्बन नक्सल कहा गया।

कोरोना के समय सरकार की हैंडलिंग पर सवाल उठाने वालों को 'अर्बन नक्सल कहा गया। गरीब, आदिवासी और कश्मीरियों की लड़ाई लड़ने वाले ज्यादा निशाने पर रहे। मेधा पाटकर से लेकर अरुंधति रॉय तक सब 'अर्बन नक्सल हैं। सामाजिक संगठनों पर पिछले कुछ वर्षों में जो कार्रवाई हुई है और विदेशी चंदे के लिए बने कानून, एफसीआरए के नियम सख्त करके गैर सरकारी संगठनों की फंडिंग रोकने का जो अभियान चला है उसके पीछे एक मुख्य कारण कथित 'अर्बन नक्सल को कमजोर करना है। देश की कई प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थाओं को 'अर्बन नक्सल से जोड़ा गया। अब इसे अमूर्त अवधारणा से निकाल कर व्यापक रूप से जनता के बीच ले जाने के लिए 'दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग हुआ है। कह सकते हैं कि एक चरण पूरा हो गया है और इस बार लाल किले से अगले चरण की घोषणा हुई है।

असल में पिछले 12 साल से सरकार और भाजपा का विरोध करने वाले लोगों के लिए अलग अलग विशेषण गढ़े जा रहे हैं और उन्हें एक खांचे में फिट करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी उनको 'खान मार्केट गैंग कहा जाता है, 'कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, कभी 'अर्बन नक्सल कहा जाता है तो अब 'दिमागी नक्सल कहा जाएगा। यहां एक पैटर्न साफ साफ दिखता है। देश के सम्भ्रांत वर्ग के साथ साथ ऐसे बौद्धिकों को निशाना बनाना है, जो सरकार की क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति पर सवाल उठाते हैं और उसकी विभाजनकारी नीतियों का विरोध करते हैं। ये दोनों सरकार की दुखती रग हैं। इनका विरोध करने वाले के लिए प्रयोग होने वाले विशेषण में नक्सली शब्द जोड़ दिया जाए तो यकीन दिलाना आसान हो जाएगा।

ध्यान रहे 'हथियारी नक्सल खत्म होने के बाद जल, जंगल, जमीन बड़े उद्योगपतियों को सौंपना आसान हो जाएगा और 'दिमागी नक्सल के कमजोर होने या समाप्त होने से सत्ता हर तरह के खतरे से सुरक्षित होगी। अब दिलचस्पी यह देखने में होगी कि पहचान का अभियान कैसे चलता है और खत्म करने की लड़ाई कैसे होती है? विचार के स्तर पर लड़ना मुश्किल होगा। तभी सवाल है कि क्या जो तरीका 'हथियारी नक्सल से लड़ने में इस्तेमाल हुआ वही 'दिमागी नक्सल के खिलाफ भी आजमाया जाएगा?

व्यंग्य

साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म सब बौने लोगों की जमात

यों इसकी वजह समाज भी है लेकिन सत्ता की ज्यादा जिम्मेदारी है कि देश में साहित्य के फलने फूलने का जो इकोसिस्टम था उसका पतन रोके। संस्कृति को बढ़ाए, निखारे। मगर संस्कृति संरक्षण के नाम पर होने वाले आयोजनों की संख्या लगातार कम होती हुई है और अगर आयोजन होता भी है तो उसमें से सौंदर्य गायब है। उलटे वह भोंडेपन का प्रदर्शन बनता जा रहा है। सोचें, एक समय देश में साहित्य के कितने केंद्र थे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और वाराणसी साहित्य और संस्कृति का बड़ा केंद्र थे तो बिहार में पटना, मध्य प्रदेश में भोपाल व जबलपुर, राजधानी दिल्ली, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता ये सब बड़े केंद्र थे। दक्षिण भारत की भाषाओं मलयालम, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में उत्कृष्ट साहित्य रचा जा रहा था। उसका अनुवाद हिंदी क्षेत्र में भी खूब बिकता था। लेकिन आज किसी कॉलेज के छात्र से समकालीन साहित्यकारों, कवियों, उपन्यासकारों के बारे में पूछा जाए या उनकी कोई कविता पढ़ने को कहा जाए तो ज्यादा संभावना है कि वह नहीं पढ़ पाएगा।

राजधानी दिल्ली से लेकर छोटे शहरों तक में भरत नाट्यम से लेकर कुचिपुड़ी और कत्थक नृत्य का आयोजन होता था। अब ऐसे आयोजन या तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल बंद हो गए हैं। नई पीढ़ी के किसी नौजवान से पूछा जाए कि वह दो चार शास्त्रीय संगीतकारों और नृत्य कला का प्रदर्शन करने वालों के नाम बताए तो गारंटी है कि वह नहीं बता पाएगा। इसे पुरानी पीढ़ी का मोह या श्रेष्ठता बोध कह कर खारिज नहीं कर सकते हैं लेकिन यह हकीकत है कि आज कहीं न तो बिस्मिल्ला खां हैं, न कहीं पंडित भीमसेन जोशी, न पंडित रविशंकर, न पंडित जसराज हैं और न किशोरी अमोनकर हैं। कोई उस्ताद अमजद अली खां या उस्ताद जाहिर हुसैन भी नहीं है। न कोई एमएफ हुसैन हो रहा है और न कोई हैदर रजा हो रहा है। साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म सब बौने लोगों की जमात हो गई है। पूरे देश में मूर्खता का महोत्सव मनाया जा रहा है। जो जितनी मूर्खतापूर्ण बात कर सकता है उसकी प्रगति के उतने ही आयाम खुलते जाएंगे। तर्क और विचार की जगह अनुशासन और आदेश पालन, भौंडेपन पर जोर हो गया है।

ब्लॉग

लूट सके सो लूट, हाँक सके सो हाँक

शंकर शरण

देश भर में हर शिक्षा संस्थान में प्रवेश, और वहाँ की परीक्षा, हर प्रश्न-पत्र, हर मूल्यांकन, आदि एक ही आफिस से करने का निर्णय लिया गया होगा। ऐसी मतिहीनता सामान्य बुद्धि से भी अटपटी लग सकती है। कि कहीं एक भी गड़बड़ी, एक भी भूल, एक की पतिताई, आदि कुछ भी देश भर के लाखों व्यक्तियों, संस्थाओं को कष्ट देगी। बार-बार परेशान करेगी।ज. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ईटन, हैरो, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आदि सभी विख्यात शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक सरकारी कार्यालय टेस्ट लेगा! ऐसा करना हर तरह से मूढ़ता पूर्ण है। पर यहाँ किया जा रहा है।

सार्वजनिक शिक्षाः गरीब की लुगाई -2

वरना, सोच कर बताएं — यह किस ने, और किस उद्देश्य से तय किया कि प्रवेश परीक्षा में शून्य अंक पाने वाला भी एक बड़े विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए प्रवेश पा सकता है? इस के उत्तर में बचाव में जितनी बातें होंगी, सब राजनीतिक और स्वार्थ, ईर्ष्या-द्वेष, लफ्फाजी का बवंडर होगा। उस में शिक्षा या ज्ञान के प्रति कोई चिंता या समझ भी लक्षित नहीं होगी। यही हैः शिक्षा का गरीब की जोरू होना! इस पर हर कोई कुछ भी बोलने, करने, थोपने, फतवे देने का अधिकारी है। मानो, यही एक क्षेत्र है जिस के लिए किसी पात्रता की जरूरत नहीं! पार्टी कार्यकर्ता से लेकर ठेकेदार तक उस में अपनी चला सकते हैं। चलाते हैं।

इसी दृष्टिकोण से देश भर में हर शिक्षा संस्थान में प्रवेश, और वहाँ की परीक्षा, हर प्रश्न-पत्र, हर मूल्यांकन, आदि एक ही आफिस से करने का निर्णय लिया गया होगा। ऐसी मतिहीनता सामान्य बुद्धि से भी अटपटी लग सकती है। कि कहीं एक भी गड़बड़ी, एक भी भूल, एक की पतिताई, आदि कुछ भी देश भर के लाखों व्यक्तियों, संस्थाओं को कष्ट देगी। बार-बार परेशान करेगी। जबकि स्थानीय, संस्थागत, राज्यवार, आदि क्षेत्राधिकार में स्वयं संपूर्ण रहने पर हर संस्था, हर परीक्षा, हर मूल्यांकन की गुणवत्ता अधिक सुरक्षित, स्पष्ट, सीमित, जिम्मेदार, और इसलिए उत्कृष्टता की संभावना भी बनी रहती है। यही पहले था भी।

यूरोप और अमेरिका के शैक्षिक संस्थानों में अभी भी वही है। उधर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ईटन, हैरो, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आदि सभी विख्यात शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक सरकारी कार्यालय टेस्ट लेगा! ऐसा करना हर तरह से मूढ़ता पूर्ण है। पर यहाँ किया जा रहा है। जो शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता को पेंदे में पहुँचा देने का अचूक उपाय है। मानो भारतीय विश्वविद्यालय रूपी फैक्ट्री से औसत कुली-कर्मचारी बनने लायक औसत माल तैयार करना हो। बस। इस से अधिक की कल्पना नहीं, चिन्ता नहीं।

वैसे भी, हर चीज का 'केंद्रीकरण एक कम्युनिस्ट-लोकतंत्री मानसिकता है। यह अंध-मानसिकता कि सब कुछ 'जनता, यानी उस के नाम पर पार्टी करेगी। फिर पार्टी के नाम पर भी एक पार्टी-कमिटी, बल्कि उस का प्रमुख, यानी अंततः एक नेता। क्या यह — एक देश एक परीक्षा — भी, 'एक देश एक चुनाव, 'एक देश एक पार्टी, और 'एक देश एक नेता की तरह की बे-सिर-पैर की कल्पना ही है? यह रूसी कम्युनिस्ट मानसिकता का ही भारतीय हिन्दू रूप जैसा है।

परन्तु, इस तरह सब कुछ एक हाथ में केंद्रित कर देना बुद्धि, विवेक, जिम्मेदारी, और गुणवत्ता का सत्यानाश करने का ही प्रबंध करना है। पूरे सोवियत कम्युनिज्म के इतिहास का सबक और क्या है? पूरे सत्तर बरस, पूरा देश चुपचाप ऊपर का मुँह देखने, और ऊटपटाँग हुक्म मानने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था! साथ ही, जो भी गड़बड़ी हो रही हो, पहले उसे छिपाना, लीपा-पोती करना, और जब बात खुल जाए तो 'विदेशियों, 'गद्दारों, या 'कामचोरों को दोष देकर फिर वैसे ही उल्टा-सीधा करते जाना। यही दशकों से सोवियत कम्युनिज्म में चलता रहा।

उसी कम्युनिज्म से स्वतंत्र भारत की अनेकानेक शासकीय नीतियाँ प्रभावित रही है। चूँकि उस से मु_ी भर राजनीतिक वर्ग असीम शक्ति, सुविधा, और भोग-विलास का अवसर पाता रहा है। इसलिए भी हर चीज पर राजकीय कब्जा करने, फिर केंद्रीकरण, आदि उसी पार्टी-एकाधिकारी मानसिकता की व्युत्पत्ति है। सब पर हम, सब कुछ पर हमारा चले। सब हमारे ताबेदार। जो विरोध करें, वह जनता के दुश्मन, या विदेशी एजेंट। इस तरह की बनी-बनाई रट, यहाँ भी सोवियत यूनियन से ही मिलती जुलती लंबे समय से रही है।

दशकों पहले कारखानों का, बैंकों का, अनेक उद्योग व्यापारों, आदि का राष्ट्रीयकरण उसी भावना में हुआ था। जब दशकों में भारी बर्बादी और लूट करके, साथ ही अंतहीन कुव्यवस्था से आगे चलना एकदम असंभव हो गया, तब जाकर किसी तरह कुछ बदलाव हुए। वह भी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की चतुराई से, लगभग चुपचाप, छिपाकर। पर यहाँ आम राजनीतिक वर्ग की वह एकाधिकारी, मनमानी, विशेषाधिकार, राजकीय संसाधनों की छीना-झपट, आदि की मानसिकता यथावत है। शिक्षा क्षेत्र उस का एक बड़ा उदाहरण है। अभी देश के विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों का आम नजारा है — 'लूट सके सो, लूट। हाँक सके सो हाँक!

बहरहाल, केंद्रीकरण करने वालों ने यह मोटी बात भी नहीं देखी कि सालो भर, नियमित रूप से, लाखों-लाख आवेदनों को जब एक केंद्रीय कार्यालय में देखा जाएगा, सैकड़ों तरह के प्रश्न पत्र एक ही जगह बनेंगे, तो यह सब अंतिम बाबुओं, क्लर्कों, सहायकों के माथे जाएगा — न शिक्षा मंत्री, न शिक्षा सचिव, न एजेंसी के डायरेक्टर वह सब देखेंगे। वे देख भी नहीं सकते! वह भौतिक रूप से असंभव है। सो, कुल मिलाकर प्रोफेसर और शिक्षकों से उन का काम छीन लिया गया, तथा इसे एक केंद्रीय ऑफिस के यांत्रिक काम में बदल डाला गया। व्यवहार में इस का अर्थ क्या हुआ?

यही कि शिक्षक, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, आदि तो अयोग्य अथवा अविश्वसनीय, या दोनों हैं। जबकि किसी केंद्रीय एजेंसी के ऑफिस का बड़ा बाबू, और भाड़े पर बुलाए गये, आते-जाते लोग विश्वसनीय तथा योग्य हैं! यह कैसी समझ है? यह भी याद रहे, उक्त प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, आदि को लाखों रूपये का वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। जबकि केंद्रीय ऑफिस के क्लर्क और ठेके वाले कंसल्टेंट्स जिन के हाथों में काम दे दिए हैं, उन्हें मामूली वेतन मिलता है। ऐसी दोहरी, पर विचित्र व्यवस्था कैसी बुद्धि है?

यह बालबुद्धि है, जो केवल भारतीय नेताओं में होती है। ध्यान देकर हमारे नेताओं का जीवनवृत्त देखें। उन में अधिकांश प्रायः जीवन में बिना कोई वास्तविक काम किए, बरसों बरस केवल लफ्फाजी, आपसी समीकरण, चापलूसी और मटरगश्ती करते हुए, विधायक से मंत्री और ऊपर चढ़ते जाते हैं। यानी, जीवन में समाज के लिए किसी ठोस, उपयोगी रोजगार करने के अनुभव से प्रायः खाली! बदले में मुख्यतः भाषण और लफ्फाजी करने का अभ्यास और अनुभव। इसलिए, जब शासन हाथ में आए तब हर विषय पर या तो कल्पना से सोचते हुए, या जिस किसी के सुझाव, विचार या विदेशियों की ऊपरी नकल से निर्णय लेते हुए, फिर सब में अपना चुनावी एवं निजी स्वार्थ व अहंकार जोड़े हुए — यानी वह सब दुर्गुण जो ब्रिटिश शासकों में एक भी नहीं थे! यह बिन्दु कुछ ध्यान देने लायक है।

भारत के बड़े भाग पर लगभग दो सौ सालों तक ब्रिटिश राज माना जाता है। अतः तुलना करना रोचक है कि सभी के सभी ब्रिटिश शासक लंबे-लंबे समय तक फौज, व्यापार, कानून, शिक्षा, आदि किसी क्षेत्र में ठोस काम का अनुभव रखते थे। इसलिए वे अपनी, और दूसरों की भी, विशेषज्ञता को समझते थे। उस का महत्व भी जानते थे। वे खामख्याली, संदेह, या किसी क्षुद्र स्वार्थ से भी चलने वाले जीव नहीं थे। जिसे जो काम मिलता था वह उसे निष्ठा और स्वाभिमान से पूरा करने में सन्नद्ध रहता था। चूँकि वह स्वयं ईमानदार और सत्यनिष्ठ होता था, इसलिए प्रायः दूसरों को भी वैसा ही समझता था। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण बिन्दु है। शासन के चरित्र और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से रोचक भी।

इसीलिए पूरा ब्रिटिश राज अपना दैनं-दिन प्रशासन मौखिक वचनबद्धता और मातहतों के साथ परस्पर विश्वास पर चलता था — संदेह पर नहीं। अर्थात, जब तक कोई मामूली देसी कुली या राजा भी, विपरीत चरित्र न दिखाए, तब तक ब्रिटिश अधिकारियों के लिए हर भारतीय भी सहज विश्वसनीय था। आपस में तो वे पक्के विश्वसनीय थे ही। उन के राज में लिखित बातें केवल कानून, नियम, योजनाएं, एकाउंट, बड़े फैसले, आदि होते थे। बाकी रूटीन चीजें मौखिक चलती थीं और उस में कभी हेर-फेर, बात बदलना, गड़बड़, आदि नहीं होता था। संक्षेप में, अंग्रेज गुणवान और चरित्रवान थे, इसलिए गुणग्राहक और चरित्र का सम्मान भी करते थे। उन में ईर्ष्या-द्वेष का अभाव, और दूसरों पर विश्वास करना कोई आकस्मिक, सांयोगिक तत्व नहीं था।

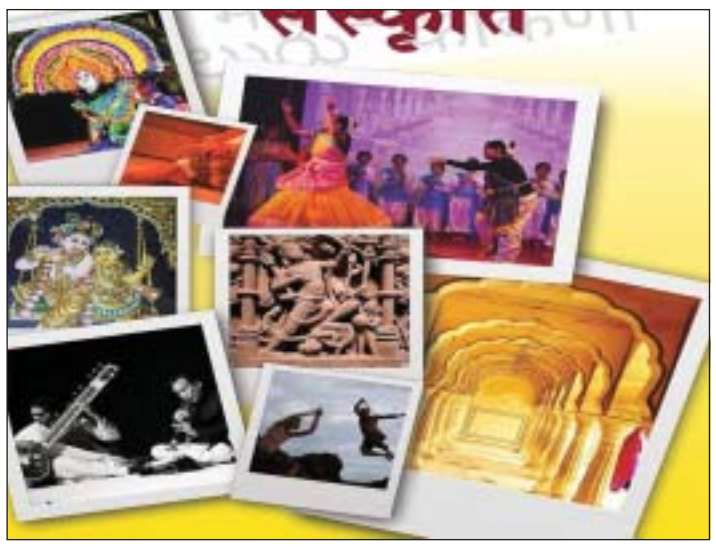

कहने का मतलब यह नहीं कि यहाँ अंग्रेज शासकों, अधिकारियों में कोई निजी स्वार्थ, पदोन्नति की चाह, अच्छी पोस्टिंग, अपने बाल-बच्चों की चिन्ता, सिफारिशों का उपयोग, आदि नहीं थी। यह सब था। पर किसी जिम्मेदारी की उपेक्षा करके, अपने वर्तमान पद के कर्तव्य के प्रति बेपरवाही से, या उस में घपला करके, अपने पद या राजकोष का दुरुपयोग करके पाया जाए — ऐसा वे प्रायः कल्पना भी नहीं करते थे! इसी बात से उन की वित्तीय ईमानदारी भी जुड़ी थी।

अतः नोट करें — कट्टर से कट्टर भारतीय राष्ट्रवादी नेता, अंग्रेजों से घृणा करने वाले भारतीय भी, किसी ने कभी अंग्रेजों पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। कभी नहीं। अंत तक नहीं। अर्थात, वायसराय से लेकर अंतिम सबाल्टर्न, यानी सब से निचला अंग्रेज सिपाही, कर्मचारी भी अपने वेतन के सिवा कुछ नहीं जानता था। यह उन के चरित्र का अंग था। यह शासक की दक्षता और विश्वसनीयता के लिए एक बड़ा तत्व है।

यहाँ जब भारतीय कर्मचारियों, अधिकारियों पर विश्वास करके अंग्रेजी साम्राज्य चलने-चलाने की बात कही जा रही है — वह भी दसियों पीढ़ियों तक — तो इस तथ्य का एक गहरा अर्थ है। चूँकि आम अंग्रेज सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण थे, इसलिए दूसरों में भी जब तक किसी अदद व्यक्ति का गलत आचरण दिख न जाए, तब तक वे उसे भी यथावत सही समझते थे। फिर, उन के राज में पुरस्कार और दंड कर्म पर तय होता था, मुँह, रंग या जाति समुदाय देख कर नहीं। तदनुरूप, भारतीय लोगों में भी, अपने अनुभव से विभिन्न जातियों, समुदायों, कबीलों, क्षेत्रों, आदि की महीन विशेषताएं जानकर अंग्रेजों ने उन के प्रति ठोस, व्यवहारिक नीतियाँ रखीं थीं। वे 'सब धान बाइस पसेरी की तरह सब को एक सा मान जिस किसी को कोई भी काम या पद नहीं दे देते थे! अपराधिक मामलों में कानून के समक्ष समानता के सिवा, वे हर भारतीय समूह की अपनी विशेषता के अनुरूप व्यवहार रखते थे। कारण वही थाः कर्तव्यनिष्ठा और अपने संपूर्ण राज्य के लक्ष्य का ध्यान। न कि किसी किताबी सिद्धांत या मतवाद या दलीयता या निजी स्वार्थ का आग्रह।

मां-बाप के अरमानों का कत्ल: जिस बेटी को दुल्हन बनते देखना था, उसकी खून से सनी लाश देख मां का फट गया कलेजा

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी जिले में जगतपुर पीजी कॉलेज में एमएससी की छात्रा श्रेया उर्फ मोनू (22) की हत्या कर दी गई। घटना उसके घर से 20 किमी दूर बच्छांव पश्चिमपुरा के एक किराये के कमरे में हुई। धारदार हथियार से गला रेतकर श्रेया को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है कि दूर के रिश्तेदार नियारडीह चोलापुर निवासी विवेक चौबे ने उसे अगवा कर हत्या की है। हत्या के बाद आरोपी ननिहाल गया। अपनी बाइक और बैग रखकर भाग निकला। उधर, बेटी की खून से सनी लाश देखकर मां का कलेजा फट गया। उसकी चीख- पुकार सुनकर लोगों की आंखें भर आईं।

परिजनों के मुताबिक, श्रेया इकलौती थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी। 22 नवंबर को उसकी रिंग

सेरेमनी और 26 फरवरी को शादी थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

प्रॉपटी के लालच में वारदात का लगाया आरोप

परिजनों ने प्रेम प्रसंग जैसी बात को नकरा। आरोप है कि विवेक जबरन श्रेया से बातचीत करता था। वीडियो कॉल पर युवती के पिता की हत्या करने की धमकी देता था। युवती ने पिता से शिकायत भी की थी। आरोपी को समझाया भी गया था। आरोपी चाहता था कि घर की अकेली लड़की है, अगर इससे शादी हो जाती है तो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। इस बीच श्रेया की शादी मिर्जापुर में तय हो गई। इस बात से नाराज विवेक चौबे ने श्रेया का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। वहीं, मृतका के मोबाइल को फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए कब्जे में लिया

मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की हैं। पुलिस अब मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और आरोपी की गतिविधियों की जांच कर रही है।

-नीतू कात्यायन, डीसीपी गोमती जोन

है। पुलिस मोबाइल में कॉल डिटेल, चैट, फोटो, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। श्रेया के पिता सुनील उपाध्याय की चंदापुर में कपड़े की दुकान है। श्रेया की मां रीता उपाध्याय ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी कॉलेज पहुंची ही नहीं थी। आशंका है कि आरोपी ने उसे रास्ते से ही अगवा किया और उसी दिन हत्या कर दी।

मकान मालिक और आरोपी के पिता हिरासत में

घटना के बाद रोहनिया पुलिस ने मकान मालिक विवेक द्विवेदी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवेक चौबे कमरे में कब से रह रहा था, छात्रा वहां कब पहुंची और हत्या के पीछे वास्तविक वजह क्या थी। रोहनिया पुलिस के अनुसार, आरोपी एक बैंक में संविदाकर्मी रहा और प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी के गांव पहुंची और आरोपी के पिता को हिरासत में लिया।

ननिहाल में छोड़े बैग में मिली चाबी

19 अगस्त की सुबह परिजन दोबारा बच्छाव पहुंचे और आसपास पूछताछ शुरू की। मकान मालिक विवेक से पता चला कि विवेक चौबे नाम का युवक दो महीने से किराये पर कमरा लेकर रह रहा था। मकान मालिक ने उसका आधार कार्ड भी परिजनों को भेजा। इससे परिजनों को युवक पर शक गहरा गया। मृतका के पिता का कहना है कि उन्होंने कमरे को खुलवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कमरा नहीं खुला। इसके बाद परिवार विवेक के ननिहाल भुवालपुर, सीखड़, मिर्जापुर पहुंचा। वहां लोगों ने बताया कि विवेक 18 अगस्त की शाम आया था। अपना बैग और मोटरसाइकिल छोड़कर चला गया था। बैग में कमरे की चाबी मिली। इसके बाद चाबी लेकर बृहस्पतिवार सुबह 10:30 बजे बच्छाव के मकान पहुंचे और कमरे विवेक चौबे का दरवाजा खोला गया। अंदर बाथरूम में श्रेया का शव खून से लथपथ पड़ा मिला।

कॉलेज जाने की बात कहकर निकली, फिर वापस नहीं लौटी

मृतका के चचेरे भाई अंशुमान के अनुसार, श्रेया 18 अगस्त को घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी। देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने कॉलेज जाकर जानकारी की। पता चला कि श्रेया कॉलेज ही नहीं आई थी। इसके बाद परिवार राजातालाब थाने पहुंचा और फिर जक्खिनी पुलिस चौकी में सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्रा के मोबाइल की लोकेशन खंगालनी शुरू की।

परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

परिजनों के अनुसार, मोबाइल की लोकेशन बच्छाव पश्चिमपुरा के एक मकान में मिली। रात 11 बजे वे पुलिस के साथ वहां पहुंचे। उस समय छात्रा का मोबाइल चालू था और लोकेशन उसी मकान से आ रही थी। परिवार को उम्मीद थी कि श्रेया कमरे के अंदर होगी। पिता सुनील उपाध्याय का आरोप है कि पुलिस ने कुछ देर जांच-पड़ताल करने के बाद दरवाजा नहीं खुलवाया। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस को सूचना देकर कमरे की तलाशी नहीं कराई गई।

न ईंट छूने दी, न नारियल फोड़ने दिया...

बीजेपी विधायक ने मंदिर में लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप, सपा बोली– क्या यही एकजुटता है

आर्यावर्त संवाददाता

मोहनलालगंज। बीजेपी की मोहनलालगंज से दलित विधायक जय देवी ने मंदिर प्रशासन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने जातिगत भेदभाव की कड़ी आलोचना की है। समजावादी पार्टी ने कहा," इस घटना ने राज्य सरकार के तहत फैली जातिगत भेदभाव की मानसिकता को सबके सामने ला दिया है।"

जय देवी ने मंदिर प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मंदिर के जीर्णोद्धार का एक कार्यक्रम था। उसके लिए भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह के दौरान उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बुधवार को वहां हुए अनुष्ठान के दौरान उन्हें न तो ईंट छूने दी गई, न ही अगरबत्ती जलाने दी गई और न ही नारियल फोड़ने दिया गया।

'बंटेंगे तो कटेंगे कहने वालों की यही एकजुटता है?'

समाजवादी पार्टी की 'बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी' के राष्ट्रीय महासचिव रामबाबू सुदर्शन ने इस घटना को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। रामबाबू ने कहा, "राज्य की राजधानी में और बीजेपी सरकार के 9 साल बाद ऐसी घटना का होना यूपी में जातिगत भेदभाव के हालात को दिखा रहा है। इस घटना ने जातिगत भेदभाव पर बीजेपी के रुख को साबित कर दिया है। ये आरोप बीजेपी की ही मौजूदा दलित विधायक ने लगाए हैं, जो दो बार बीजेपी सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कौशल किशोर की पत्नी हैं। अगर ये किसी दूसरी पार्टी की विधायक होतीं, तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी इस पूरी घटना को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती।"

सुदर्शन ने कहा, " ये घटना न केवल मौजूदा दलित विधायक की दुर्दशा को जाहिर करती है, बल्कि राज्य और देश के करोड़ों दलितों की भावनाओं और जज्बातों को भी दिखाने के लिए काफी है। बीजेपी और आरएसएस 'बंटेंगे तो कटेंगे' जैसे नारों के साथ हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। क्या बीजेपी इसी तरह हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है? ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या बीजेपी दलितों को हिंदू मानती भी है या नहीं?"

थप्पड़ कांड, मारपीट और विवादों की हैट्रिक... जानें क्यों गंवानी पड़ी अविनाश पांडेय को मेरठ एसएसपी की कुर्सी?

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। उत्तर प्रदेश शासन ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अविनाश पांडेय को पद से हटा दिया है। 2015 बैच के IPS अधिकारी अविनाश पांडेय को अब पुलिस महानिदेशक (DGP) मुख्यालय, लखनऊ से संबद्ध किया गया है। शासन ने झांसी के SSP रहे IPS अधिकारी बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ का नया SSP नियुक्त किया है।

अविनाश पांडेय का तबादला ऐसे समय में हुआ है, जब पिछले डेढ़ महीने के भीतर मेरठ में पुलिस की कार्रवाई और उनके व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर लगातार गंभीर विवाद सामने आ रहे थे। विवादों की शुरुआत जुलाई में ललिता गौतम हत्याकांड के दौरान हुई। कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हुआ, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी

दौरान SSP अविनाश पांडेय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह एक प्रदर्शनकारी/अधिवक्ता को थप्पड़ मारते दिखे।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत विपक्षी नेताओं ने पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सरकार और एसएसपी को आड़े हाथों लिया। इस मामले में एसएसपी और करीब 50 पुलिसकर्मियों के खिलाफ SC-ST कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि, अविनाश पांडेय ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई को साक्ष्यों पर आधारित और सही ठहराया था।

किसान नेता से मारपीट और थर्ड डिग्री का आरोप

थप्पड़ कांड का विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि अगस्त में भारतीय किसान यूनियन (बीआर आंबेडकर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ। दिग्विजय भाटी ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए। भाटी का आरोप था कि वे अपने साथी के साथ एक गैंगस्टर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग लेकर SSP कार्यालय गए थे। वहां SSP ने नाराज होकर उनके साथ मारपीट की और बाद में एसओजी (SOG) दफ्तर ले जाकर भी पिटाई की। इस घटना के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान भी थाने पहुंचे थे और हंगामा बढ़ा था।

अविनाश पांडेय ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा था कि दिग्विजय भाटी एक हिस्ट्रीशीटर के साथ दफ्तर आए थे और विवाद कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें हिरासत में लिया गया था। उन्होंने किसी भी तरह की पिटाई या थर्ड डिग्री से इनकार किया था।

शासन का सख्त फैसला

लगातार दो बड़े विवादों, पुलिसिया व्यवहार पर उठते सवालों और विपक्षी दलों के दबाव के बीच आखिरकार शासन ने अविनाश पांडेय को फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे रुटीन प्रशासनिक फेरबदल बताया जा रहा है, लेकिन गलियारों में इसे विवादों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। अब मेरठ की कमान IPS बीबीजीटीएस मूर्ति के हाथों में होगी।

'सुहागरात से शुरू हुई सनक, बीमार मां को भी पीटा...', लखनऊ केस में प्रज्ञा मिश्रा ने खोली जीजा मानस की पोल

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ के चर्चित ICICI बैंक अधिकारी दिव्या मिश्रा हत्याकांड और पति मानस वाजपेयी के सुसाइड केस में नया और सनसनीखेज अपडेट सामने आया है। कत्ल के बाद मानस द्वारा अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर लगाए गए आरोपी मैसेज और सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बाद, दिव्या की बहन और मशहूर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने चुप्पी तोड़ी है। प्रज्ञा ने एक भावुक और तीखी फेसबुक पोस्ट के जरिए मानस को "साइको हत्यारा" करार देते हुए उसकी क्रूरता की परतें खोली हैं।

प्रज्ञा मिश्रा ने अपनी पोस्ट में खुलासा किया कि मानस की सनक शादी की पहली रात से ही शुरू हो गई थी। शादी की पहली ही रात मानस ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई और दिव्या के सामने आधा खर्च उठाने की

शर्त रख दी। दिव्या ने पहले तो इसे मान लिया, लेकिन बीते एक साल से जब उसने अपने हिस्से का खर्च देना बंद किया, तो मानस को लगने लगा कि उसके साथ 'चीटिंग' हो रही है।

"ब्लिंकिट से आए खराब टमाटर पर भी पीटता था"

प्रज्ञा ने मानस की मानसिक स्थिति और घरेलू हिंसा का जिक्र करते हुए लिखा कि वह बेहद छोटी-छोटी बातों पर दिव्या के साथ बेरहमी से मारपीट करता था। अगर ब्लिंकिट से मंगाया गया कोई टमाटर भी खराब निकल जाता था, तो वह दिव्या को यह कहकर पीटता था कि तूने सही से ऑर्डर कैसे नहीं किया। इसके अलावा प्रज्ञा ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि मानस और उसकी बहन (तुलिका) ने मिलकर अपनी बीमार मां के साथ भी इस कदर मारपीट की थी कि उनका निधन हो गया था।

असुरक्षा, पीछा करना और एक्सीडेंट का खौफ

फेसबुक पोस्ट में बताया गया कि मानस अक्सर दिव्या का पीछा करता था। अत्यधिक तनाव (स्ट्रेस) के कारण कुछ समय पहले दिव्या का एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसमें उसके हाथ और पैर टूट गए थे। डेढ़-दो महीने के लंबे इलाज के बाद दिव्या ने हाल ही में लंगड़ाकर चलना शुरू किया था और घटना के दिन भी वह दर्द में ही घर से निकली थी। इसके बावजूद दिव्या अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। उसने अपने हाथ पर बना मानस के नाम का टैटू भी नहीं मिटवाया था और वह इस बार भी हरतालिका तीज का व्रत रखने की तैयारी कर रही थी।

बीमार मां अनजान

इस दर्दनाक हादसे के बीच दिव्या की बीमार मां को अब तक अपनी बेटी की मौत की खबर नहीं दी गई है। उन्हें केवल यही बताया गया है कि दिव्या की हालत गंभीर है।

डेमो शिक्षण से बच्चों में सीखने की बढ़ी रुचि

जौनपुर। पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय डेडुवाना केराकत में कक्षा-3 में सत्र परीक्षा के बाद एआरपी प्रदीप कुमार यादव द्वारा डेमो शिक्षण कराया गया। इस दौरान बच्चों को वार्मअप गतिविधि के रूप में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से जोड़ते हुए शिक्षण कराया गया। गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक तरीके से समझा।एआरपी ने विद्यालय के भौतिक परिवेश एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में हुए सकारात्मक परिवर्तन की सराहना करते हुए प्रधानाध्यापक एवं पूरे विद्यालय परिवार को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों के अनुकूल वातावरण और शिक्षकों के निरंतर प्रयास से शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं।एआरपी ने शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय आईसीटी पुरस्कार एवं राज्य स्तरीय आदर्श पाठयोजना पुरस्कार के साथ ही जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।

मनाया हजरत हम्जा चिश्ती का उर्स

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। नगर के पचहटियां स्थित विशेषरपुर दरगाह पर हजरत हम्जा चिश्ती का 551वां सालाना उर्स ए मुबारक बड़ी अकीदत के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे गुस्ल-ए-मजार से हुई। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष शमशेर कुरैशी और कन्वीनर अरशद कुरैशी ने मजार पर चादर चढ़ाई। सुबह 9 बजे कुरआन ख्वानी हुई। इसके बाद जलसा ए सिरातुन्नबी स.अ. व में मौलाना कयामुद्दीन ने सीरत को अपनाने की बात कही। मौलाना नसीम रजा ने नात पेश की। जोहर की नमाज के बाद भव्य लंगर का आयोजन किया गया जिसमें सभी जायरीन को मुफ्त भोजन कराया गया। शाम 4 बजे सेंट पैट्रिक स्कूल के सामने से जुलूस-ए-चादर निकाला गया। जिसमें फन ए सिपहगरी के अखाड़े भी शामिल हुए। सायं 7 बजे कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का आयोजन दरगाह प्रांगण में किया

गया ।ँ ओबैदा शिराजी अध्यक्ष मरकजी सीरत कमेटी की अध्यक्षता में किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉ.सरफराज खान चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पंचायत जफराबाद एवं मुख्य वक्ता के तौर पर संजीव यादव एडवोकेट मुख्य ट्रस्टी श्री गणपति पूजा महासमिति उपस्थित रहे। जहां संयोजक अरशद कुरैशी ने सभी अतिथियों का साफा व गुलपोशी करके स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य ट्रस्टी संजीव यादव ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाते हैं। मुख्य अतिथि ने कहा कि बड़ी संख्या में जायरीनों की मौजूदगी बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। अध्यक्षता कर रहे ओबैदा शिराजी ने कहा कि बुजुर्गों वालियों ने सदैव एकता भाईचारा और इंसानियत का पाठ पढ़ाया आज आवश्यकता है कि हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलें।

50 हजाररिश्वत का एआरटीओ के बाबू पर आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। एआरटीओ कार्यालय में कथित घूसखोरी को लेकर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक वाहन मालिक ने रजिस्ट्रेशन नहीं होने से नाराज होकर अपने पांच ट्रकों को एआरटीओ कार्यालय के सामने ही लाकर खड़ा कर दिया। एक साथ पांच ट्रकों के सड़क पर खड़े होने से मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई और कार्यालय परिसर में भी अफरा-तफरी मच गई। वाहन मालिक ने रजिस्ट्रेशन बाबू पर 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घूस नहीं देने के कारण पिछले एक सप्ताह से उसके ट्रकों का रजिस्ट्रेशन जानबूझकर लटकाया जा रहा है।वाहन मालिक मडियाहूं कस्बे के निवासी विनय सिंह का आरोप है कि उसने अपने पांचों ट्रकों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियमानुसार आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा

कर दिए थे। इसके बावजूद करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। आरोप है कि कार्यालय में तैनात रजिस्ट्रेशन बाबू गणेशदत्त द्वारा कथित तौर पर प्रत्येक काम को आगे बढ़ाने के लिए 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। वाहन मालिक का कहना है कि रिश्वत देने से इनकार करने पर उसकी फाइल को लगातार टाल दिया गया। जब शिकायतकर्ता अपने पांचों ट्रकों को लेकर सीधे एआरटीओ कार्यालय के सामने पहुंच गया। ट्रकों को सड़क पर खड़ा किए जाने से देखते ही देखते जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कार्यालय में भी इसकी चर्चा तेज हो गई। आरआई के अनुयार संबंधित बाबू गणेशदत्त हाईकोर्ट गए हैं, जबकि एआरटीओ लखनऊ गए हुए हैं। मामला तूल पकड़ता देख आनन-फानन में वाहन मालिक की रजिस्ट्रेशन संबंधी फाइल दूसरे बाबू को सौंप दी गई। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई।

वृंदावन में मॉल की शटरिंग गिरने से 3 की मौत, न सेफ्टी गियर, न कोई इंतजाम... जान दांव पर लगाकर काम कर रहे थे मजदूर

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। मथुरा में वृंदावन के एक निर्माणाधीन मॉल में आज सुबह एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। ओमेक्स कोर्टयार्ड मॉल में ढलाई कार्य के दौरान अचानक शटरिंग गिर जाने से मलबे में दबकर तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मॉल में सुबह के समय छत की ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान तड़के करीब 6:00 बजे अचानक पूरी शटरिंग भरभराकर नीचे गिर गई। हादसे के वक्त वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और सुरक्षाकर्मी मौके पर दौड़े।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की

गाड़ियां राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गईं। हादसे में जान गंवाने वाले एक मृतक की पहचान नेपाल निवासी 42 वर्षीय शिवराम के रूप में हुई है। मलबे से दो अन्य मजदूरों के शव भी बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान पश्चिम बंगाल निवासी 28 वर्षीय रफ्यूल और 30 वर्षीय आलम के रूप में हुई है।

ताक पर थी सुरक्षा!

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक अन्य मजदूर, पश्चिम बंगाल निवासी 45 वर्षीय दिलदार को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहद नाजुक हालत में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है।

घटना स्थल पर मौजूद लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था। कार्यस्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम या सेफ्टी गियर उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण यह भीषण हादसा हुआ।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में कुल तीन मजदूरों की मौत हुई है और एक घायल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राहत कार्य पूरा होने के बाद अब घटना के कारणों की जांच की जा रही है कि निर्माण कार्य में किस स्तर पर लापरवाही बरती गई।

सुबह खाली पेट पानी पीने से क्या सच में मिलते हैं फायदे?

सुबह खाली पेट पानी पीने की आदत कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या वाकई इससे शरीर को फायदे मिलते हैं? आइए जानते हैं।

सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना कई लोगों की रोज की आदत होती है। पानी शरीर के लिए जरूरी है और इसकी कमी होने पर शरीर के काम करने के तरीके पर असर पड़ सकता है। दिन की शुरुआत में पानी पीने को लेकर भी लोगों के बीच कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे सुबह की हेल्दी आदत मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं।

सुबह पानी पीने को लेकर सोशल मीडिया और आम बातचीत में कई दावे किए जाते हैं। इन्हीं दावों की वजह से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि सुबह खाली पेट पानी पीना कितना सही है और क्या इसे लेकर बताई जाने वाली हर बात सच है। ऐसे में इस आदत से जुड़ी सही जानकारी समझना जरूरी है। आइए जानते हैं सुबह खाली पेट पानी पीने को लेकर क्या सच है।

सुबह खाली पेट पानी पीना फायदेमंद है या नहीं?

Healthline के मुताबिक, सुबह उठकर पानी पीना अच्छी आदत है, क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी पूरी करने में मदद मिलती है। लेकिन सिर्फ सुबह खाली पेट पानी पीने से कोई ऐसा खास फायदा मिलता है, जो दिन में किसी और समय पानी पीने से नहीं मिलता, इसका पक्का सबूत नहीं है। शरीर को पानी की जरूरत पूरे दिन होती है।

अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो थकान, ध्यान लगाने में परेशानी और याददाश्त पर असर पड़ सकता है। पर्याप्त पानी पीने से इन समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। पानी वजन कम करने में भी थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ सुबह पानी पीना जरूरी नहीं है। इसी तरह सुबह ठंडा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज होता है, इसका भी मजबूत सबूत नहीं है। इसलिए सुबह पानी पी सकते हैं, लेकिन पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना ज्यादा जरूरी है।

सुबह पानी पीते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सुबह उठकर पानी पीते समय एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। अपनी प्यास और शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी पिएं। बहुत ठंडा पानी पीना जरूरी नहीं है, सामान्य तापमान का पानी भी लिया जा सकता है। अगर सुबह पानी पीने से पेट में भारीपन या किसी तरह की परेशानी होती है, तो अपनी सुविधा के अनुसार समय बदल सकते हैं।

पानी पीने के लिए किसी खास समय या तय मात्रा को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है कि पूरे दिन पर्याप्त पानी पीते रहें। अगर किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने पानी की मात्रा कम या ज्यादा रखने को कहा है, तो उसी सलाह का पालन करें। सुबह पानी पीना अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन इसे सेहत के लिए जरूरी नियम नहीं मानना चाहिए।

ब्रेड से बनाएं ये टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स, मिनटों में होंगे तैयार

ब्रेड से बनने वाले स्नैक्स अक्सर बच्चों और बड़ों को पसंद आते हैं। इन्हें कम समय में तैयार किया जा सकता है, इसलिए सुबह के नाश्ते या शाम की भूख के लिए ये एक आसान ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि, ब्रेड खरीदते समय उसके प्रकार पर ध्यान देना जरूरी है। सफेद ब्रेड की जगह होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड लेना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर और कुछ जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं।

होल व्हीट ब्रेड में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है। वहीं, ब्रेड के साथ सब्जियां, पनीर, अंडा या दूसरी हेल्दी चीजें मिलाने से स्नैक को ज्यादा पौष्टिक बनाया जा सकता है। अगर आप भी ब्रेड से कुछ स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, तो इसे अलग-अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं ब्रेड से बनने वाली कुछ आसान और टेस्टी स्नैक्स रेसिपीज, जिन्हें आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

ब्रेड से बनाएं ये 5 क्रिस्पी स्नैक्स

वेज ब्रेड टोस्ट

ब्रेड पर बारीक कटी शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और गाजर रखें। ऊपर थोड़ा पनीर डालकर तवे पर धीमी आंच में सेंकें, जब तक ब्रेड क्रिस्पी न हो जाए। सब्जियों से फाइबर, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जबकि पनीर से प्रोटीन और कैल्शियम मिल सकता है।

ब्रेड पिज्जा

ब्रेड पर टोमैटो सॉस की हल्की परत लगाएं और ऊपर प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ा चीज डालें। इसे तवे या ओवन में तब तक सेंकें, जब तक ब्रेड कुरकुरी और चीज पिघल न जाए। सब्जियों से कई पोषक तत्व मिलते हैं और चीज से प्रोटीन व कैल्शियम मिल सकता है।

पनीर ब्रेड रोल

ब्रेड के किनारे हटाकर इसे बेल लें। इसमें पनीर, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज की फिलिंग रखें और रोल बनाकर तवे पर हल्के तेल में सेंकें। पनीर से प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, जबकि सब्जियों से फाइबर और कई विटामिन मिल सकते हैं। इससे पेट भी ज्यादा देर तक भरा रह सकता है।

वेज ब्रेड कटलेट

ब्रेड को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उबले आलू, गाजर, मटर और मसालों के साथ मिलाएं। इसकी छोटी टिक्की बनाकर तवे पर थोड़ा तेल लगाकर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेंकें। सब्जियों से फाइबर, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तवे पर कम तेल में बनाने से स्नैक हल्का रखा जा सकता है।

एग ब्रेड टोस्ट

एक अंडे को फेंटकर उसमें प्याज, टमाटर, धनिया और हल्के मसाले मिलाएं। ब्रेड को इस मिश्रण में हल्का डुबोकर तवे पर दोनों तरफ से सेंकें। अंडे से प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। यह स्नैक नाश्ते में लिया जा सकता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है।

ब्रेड से स्नैक्स बनाते समय किन बातों का रखें ध्यान

ब्रेड खरीदते समय होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड लेना बेहतर है, क्योंकि इसमें सफेद ब्रेड की तुलना में ज्यादा फाइबर मिल सकता है। पैकेट पर पोषक तत्वों, चीनी और नमक की मात्रा भी देख लें। स्नैक्स बनाते समय बहुत ज्यादा तेल, मक्खन या चीज डालने से बचें।

सब्जियों को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। ब्रेड को बहुत ज्यादा जलाकर न खाएं। पनीर और चीज की मात्रा जरूरत के हिसाब से रखें। स्नैक्स को ज्यादा देर तक बाहर रखने के बजाय बनाकर तुरंत खाना बेहतर है।

कौन से फूड्स एक साथ कई न्यूट्रिएंट्स देते हैं?

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग-अलग विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। ये न्यूट्रिएंट्स शरीर के कई जरूरी कामों में मदद करते हैं। विटामिन ए आंखों और त्वचा की सेहत के लिए जरूरी है, जबकि विटामिन बी शरीर को एनर्जी बनाने और नसों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। विटामिन सी इम्युनिटी और घाव भरने में मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी है, वहीं विटामिन ई शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद करता है।

मिनरल्स भी शरीर के लिए उतने ही जरूरी हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में मदद करता है, आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी है और जिंक इम्युनिटी व घाव भरने में मदद करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों के काम में मदद करता है, जबकि पोटैशियम शरीर में पानी और ब्लड प्रेशर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इन सभी पोषक तत्वों की जरूरत पूरी करने के लिए संतुलित डाइट लेना जरूरी है। आइए जानते हैं कौन से फूड्स एक साथ कई न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं और इन्हें हेल्दी तरीके से कैसे खाएं।

एक साथ कई न्यूट्रिएंट्स देते हैं ये हेल्दी फूड्स

बादाम

Mayo Clinic के अनुसार, बादाम में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट और विटामिन ई पाए जाते हैं। इनमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट दिल की सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। फाइबर पेट की सेहत को सपोर्ट करता है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के लिए जरूरी हैं।

सेब

सेब में फाइबर पाया जाता है। फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें विटामिन सी और पौधों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं।

बीन्स

बीन्स में प्रोटीन और फाइबर के साथ आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फोलेट, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों के लिए जरूरी है, जबकि आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और फोलेट सेल्स के काम में मदद करता है।

ब्लूबेरी

ब्लूबेरी में एंथोसाइनिन जैसे पौधों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इनमें विटामिन के, विटामिन सी और फाइबर भी होता है। ये पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं, आंखों और पाचन की सेहत को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं।

ब्रोकली

ब्रोकली में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और पौधों से मिलने वाले कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए जरूरी है। विटामिन सी इम्युनिटी को सपोर्ट करता है और शरीर को आयरन सोखने में भी मदद करता है।

सैल्मन फिश

सैल्मन फिश में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड EPA और DHA पाए जाते हैं। ओमेगा-3 दिल और दिमाग की सेहत को सपोर्ट कर सकता है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों और दूसरे टिश्यू के लिए जरूरी होता है।

पालक

पालक में विटामिन ए और सी, पोटैशियम, आयरन और फोलेट पाए जाते हैं। इसमें बीटा-कैरोटीन, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे पौधों से मिलने वाले पोषक तत्व भी होते हैं। ये आंखों की सेहत और शरीर की कोशिकाओं के सही काम में मदद कर सकते हैं।

शकरकंद

शकरकंद में बीटा-कैरोटीन, पोटैशियम, विटामिन ए , कुछ बी विटामिन और फाइबर पाए जाते हैं। बीटा-कैरोटीन से शरीर विटामिन ए बना सकता है, जो आंखों और सेल्स के लिए जरूरी है। फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है।

इन फूड्स को हेल्दी तरीके से कैसे खाएं?

इन फूड्स को डाइट में शामिल करते समय इन्हें ज्यादा तेल, नमक, चीनी या मक्खन के साथ लेने से बचें। बादाम और दूसरे नट्स बिना नमक वाले चुनें और इनकी मात्रा का ध्यान रखें, क्योंकि इनमें कैलोरी ज्यादा हो सकती है। फलों को जूस की जगह पूरा खाना बेहतर है, ताकि फाइबर भी मिले। बीन्स को कम नमक के साथ पकाएं।

ब्रोकली और पालक को बहुत ज्यादा पकाने के बजाय हल्का पकाकर खा सकते हैं। सैल्मन फिश को तलने के बजाय बेक या ग्रिल करके खाना बेहतर है। शकरकंद को उबालकर या बेक करके खा सकते हैं। कुल मिलाकर, अलग-अलग तरह के पोषक तत्व पाने के लिए डाइट में कई तरह के हेल्दी फूड्स शामिल करना बेहतर है।

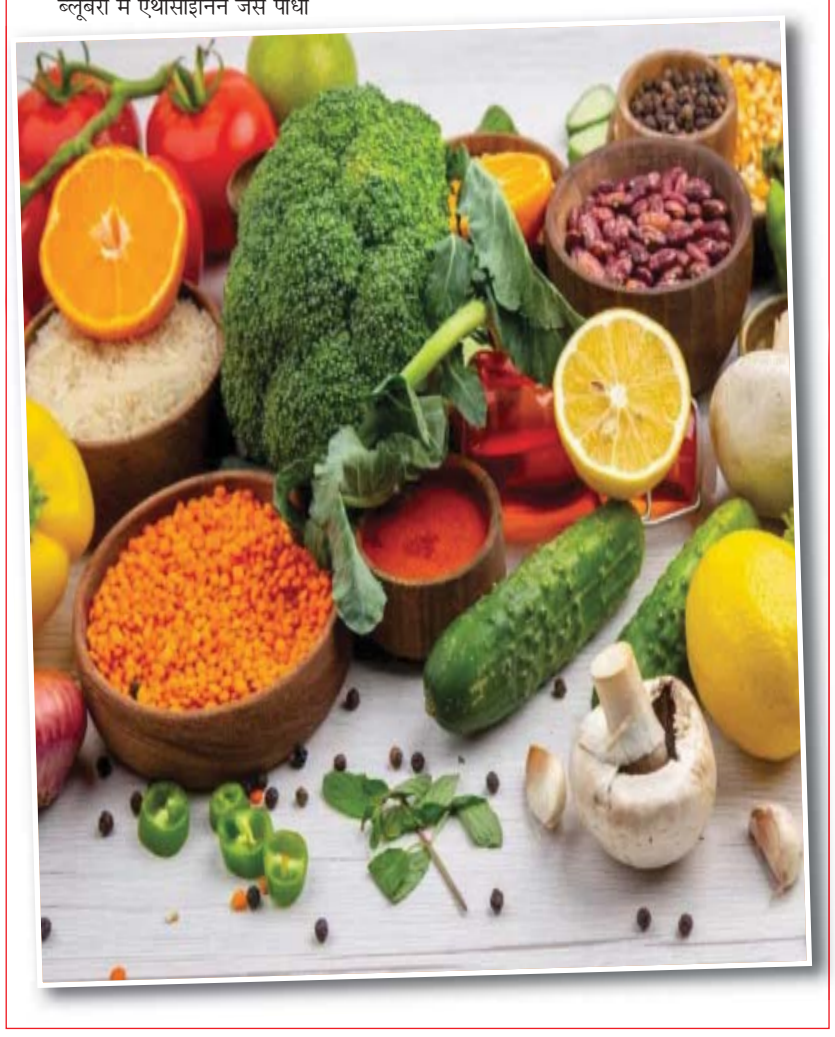

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में नरमी से भारतीय शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 558 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के ऊपर

वैश्विक बाजार से मिल रहे सकारात्मक संकेतों और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में गिरावट के चलते सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान में खुला। घरेलू बाजार में यह तेजी लगातार सात सत्रों की गिरावट के बाद लौटी है।

इस दौरान, बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,909.68 से 0.72 प्रतिशत यानी 558.77 अंक उछलकर 77,468.45 पर खुला, और दिन के कारोबार में एक समय इसने 0.76 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,494.79 का उच्चतम स्तर और 77,375.75 का निम्नतम स्तर छुआ।

वहीं, एनएसई निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 24,078.30 से 0.61 प्रतिशत यानी 147.15 अंक की बढ़त के साथ 24,225.45 पर खुला, जो इंट्रा-डे ट्रेडिंग का उच्चतम स्तर रहा, जबकि 24,184.55 का स्तर दिन का निम्नतम स्तर रहा।

हालांकि खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 532.60 अंक या 0.69 प्रतिशत उछलकर 77,442.28 पर ट्रेड करता नजर आया, तो वहीं निफ्टी 50 121.10 (0.50 प्रतिशत) अंक की बढ़त के साथ 24,199.40 पर कारोबार करता नजर आया।

इस दौरान, व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में क्रमशः 0.56 प्रतिशत और 0.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी के लगभग सभी इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड करते नजर आए। निफ्टी आईटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी एफएमसीजी में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा, मिडस्मॉल आईटी और टेलीकॉम तथा मेटल शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली।

विश्लेषकों के अनुसार, बाजार पिछले 12 कारोबारी सत्रों से दबाव में था। हालांकि अब तकनीकी संकेतक यह दर्शा रहे हैं कि बाजार में अल्पकालिक सुधार की संभावना बन रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि शॉर्ट कवरिंग और बेहतर वैश्विक संकेतों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक, निफ्टी ने 24,060 के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से मजबूत वापसी की है। चार घंटे के चार्ट पर तेजी का संकेत देने वाला पैटर्न बनने से बाजार में रिकवरी की संभावनाएं बढ़ी हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि निफ्टी 24,200 से 24,260 के दायरे के ऊपर टिकता है, तो इसमें और तेजी आ सकती है तथा सूचकांक 24,380 से 24,540 के स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं 24,060 का स्तर फिलहाल महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में बना हुआ है। यदि यह स्तर टूटता है, तो निफ्टी में गिरावट बढ़कर 23,575 तक जा सकती है।

निवेशक गतिविधि के मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में खरीदारी जारी रखी और बुधवार को 407 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) लगातार सातवें सत्र खरीदार रहे और उन्होंने 3,973 करोड़ रुपए का निवेश किया।

वैश्विक बाजारों से भी समर्थन मिला। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका दीर्घकालिक ट्रेजरी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर विचार कर रहा है, जिससे उधारी लागत कम करने में मदद मिल सकती है। इस खबर के बाद वैश्विक बॉन्ड बाजार और इक्विटी बाजारों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला।

एशियाई शेयर बाजारों में भी मजबूती रही। वहीं अमेरिकी बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 सूचकांक 0.21 प्रतिशत और नैस्डैक 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

इस बीच, अमेरिका-ईरान तनाव के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं। ब्रेंट कच्चा तेल लगभग 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) का भाव 84.52 डॉलर प्रति बैरल के करीब रहा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक बॉन्ड यील्ड में नरमी बनी रहती है और विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहती है, तो भारतीय शेयर बाजार में निकट अवधि में और सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति निवेशकों की निगाह में बनी रहेंगी।

नए पिक्सल 11 सीरीज के साथ भारत पर बड़ा दांव लगा रहा गूगल, स्थानीय विनिर्माण और एआई पर बढ़ा फोकस

अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल ने भारत में अपनी नई पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च करते हुए देश को अपने वैश्विक विस्तार और विनिर्माण रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के संकेत दिए हैं। ऐसे समय में जब रिपोर्ट्स में गूगल द्वारा चीन से पिक्सल स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और वायरलेस ईयरबड्स के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से बाहर स्थानांतरित करने की बात कही जा रही है, भारत कंपनी के लिए एक प्रमुख विनिर्माण और विकास केंद्र के रूप में उभर रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, भारत सरकार की स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों और तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र ने गूगल जैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांडों को आकर्षित किया है। गूगल पहले ही भारत में चुनिंदा पिक्सल स्मार्टफोन मॉडल का उत्पादन शुरू कर चुका है। अगस्त 2024 में पिक्सल 8 के साथ स्थानीय उत्पादन की शुरुआत हुई थी, और इसके बाद कंपनी ने देश में अपनी विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल ने नई पीढ़ी के पिक्सल उपकरणों के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी की है। इससे भारत को वैश्विक स्मार्टफोन आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूत स्थान मिलने की उम्मीद है।

गूगल इंडिया में डिवाइसेज एंड सर्विसेज के प्रबंध निदेशक मितुल शाह ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य हमेशा उपभोक्ताओं की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना रहा है, ताकि वे तकनीक का सहज अनुभव प्राप्त कर सकें।

उन्होंने कहा, हमारा ध्यान भारतीय उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतों से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। पिक्सल 11 श्रृंखला इसी सोच का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें विशेष रूप से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर हार्डवेयर, एआई और दीर्घकालिक उपयोगिता को एक साथ जोड़ा गया है।

गूगल ने कहा कि वह बेहतर वित्तीय विकल्पों, सर्विस नेटवर्क के विस्तार और पिक्सल पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर निवेश के माध्यम से भारत में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है।

पिक्सल की 11वीं पीढ़ी के स्मार्टफोन अधिक टिकाऊ हार्डवेयर, उन्नत कैमरा प्रणाली और अधिक सक्रिय जेमिनी एआई सुविधाओं के साथ पेश किए गए हैं। इन उपकरणों को कंपनी के नए गूगल टेंसर जी6 प्रोसेसर से शक्ति मिलती है।

नई सीरीज में पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल 11 प्रो एक्सएल और पिक्सल 11 प्रो फोल्ड शामिल हैं। ये सभी उपकरण गूगल के नवीनतम जेमिनी नैनो मॉडल पर आधारित एआई क्षमताओं से लैस हैं।

कंपनी के अनुसार, नया टाइटन एम3 सुरक्षा चिप और विशेष रूप से विकसित टेंसर जी6 प्रोसेसर मिलकर अब तक की सबसे मजबूत और सक्रिय सुरक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं। इससे उपयोगकर्ताओं को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बेहतर स्तर का लाभ मिलेगा।

भारत में पिक्सल 11 की शुरुआती कीमत 89,999 रुपए, पिक्सल 11 प्रो की 1,19,999 रुपए, पिक्सल 11 प्रो एक्सएल की 1,34,999 रुपए और पिक्सल 11 प्रो फोल्ड की 1,86,999 रुपए रखी गई है।

इसके साथ ही कंपनी ने पिक्सल वॉच 5 भी लॉन्च की है, जिसकी 41 मिमी संस्करण की कीमत 42,900 रुपए और 45 मिमी संस्करण की कीमत 45,900 रुपए निर्धारित की गई है।

धेनु बिल्डकॉन ने 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज का जाल बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए का बार-बार किया इस्तेमाल : सेबी

मुंबई। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आरोप लगाया है कि धेनु बिल्डकॉन इंफ्रा लिमिटेड ने आपस में जुड़ी संस्थाओं के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए 25 करोड़ रुपए की मूल राशि को बार-बार इधर-उधर घुमाया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए का वास्तविक असुरक्षित कर्ज मिला था।

ये आरोप सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में लगाए गए हैं। नियामक के अनुसार, इस कथित व्यवस्था को सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन ने संचालित किया और इसमें धेनु बिल्डकॉन तथा कंपनी से जुड़ी कई संस्थाएं शामिल थीं।

सेबी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान धेनु बिल्डकॉन को कथित तौर पर सात संस्थाओं से 1,000 करोड़ रुपए का असुरक्षित कर्ज मिला। इसके बाद कंपनी ने दिसंबर 2025 में इन छह संस्थाओं को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए कथित 840 करोड़ रुपए के कर्ज को इक्विटी में बदल दिया। हालांकि, लेनदेन में कथित रूप से शामिल संस्थाओं के बैंक खातों की जांच से पता चला कि कथित 1,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रवाह आपस में जुड़ी संस्थाओं के खातों के जरिए 25 करोड़ रुपए की एक ही मूल राशि को बार-बार अलग-अलग स्तरों पर घुमाने और प्रसारित करने से तैयार किया गया था। नियामक ने आगे आरोप लगाया कि शुरुआती 25 करोड़ रुपए की राशि भी अन्य जुड़ी हुई संस्थाओं से जुड़े संदिग्ध फंड लेनदेन से आई थी।

फंड के ट्रेल के अपने विश्लेषण के आधार पर सेबी ने कहा कि उसने प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला है कि कथित कर्ज वास्तविक लेनदेन नहीं थे।

इसके परिणामस्वरूप, नियामक ने आरोप लगाया कि 840 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वास्तविक वित्तीय लेनदेन के बिना किया गया था। सेबी ने धेनु बिल्डकॉन, कर्जदाता और तरजीही आवंटन पाने वाली संस्थाओं तथा कंपनी से धन प्राप्त करने वाली अन्य संस्थाओं के बीच कई संबंधों की भी पहचान की। इन संबंधों में एक जैसे पते, निदेशक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और बैंक शाखाएं शामिल थीं। इसके अलावा, इन संस्थाओं के बीच बड़े पैमाने पर एक-दूसरे की शेयर हिस्सेदारी भी थी।

नियामक के अनुसार, इस नेटवर्क का हिस्सा रही संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन में थीं। सेबी ने एक असंबंधित मामले में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान बरामद चैट संदेशों और कॉल रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। नियामक ने कहा कि इनसे इस नेटवर्क पर कथित रूप से किए जा रहे नियंत्रण के सबूत मिले।

इन संस्थाओं के पंजीकृत कार्यालयों के भौतिक निरीक्षण के दौरान भी चिंताएं सामने आईं। सेबी ने कहा कि ऐसा प्रतीत हुआ कि इन संस्थाओं की वास्तविक भौतिक मौजूदगी और व्यावसायिक गतिविधियों का ठोस आधार नहीं था। नियामक ने आगे कहा कि कथित लेनदेन ऐसे समय में हुए जब धेनु बिल्डकॉन के बाजार मूल्यांकन में नाटकीय वृद्धि हुई थी।

सोमालिया तट पर तुर्की के हथियारों से लदा जहाज हाईजैक, 6 भारतीय समेत 10 क्रू फंसे

सोमालिया। अफ्रीकी देश सोमालिया के पुंटलैंड तट के नजदीक समुद्री लुटेरों ने कैमरून के झंडे वाले एक कार्गो शिप का अपहरण कर लिया, जिस पर 6 भारतीय भी सवार थे। सोमालिया के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को M/V LUTUF नाम के शिप पर तुर्की के हथियार लदे थे और समुद्री लुटेरे इस जहाज का अपहरण कर नुगाल तट की ओर ले गए हैं।

अधिकारी ने बताया कि पुंटलैंड के आइल जिले में मर्राया के पास समुद्र में कार्गो शिप का अपहरण किया गया। उन्होंने बताया कि पोलर मूवमेंट शिपिंग के शिप में मोगादिशु स्थित तुर्की के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए हथियारों के साथ-साथ कम्युनिकेशन और सैटेलाइट इक्विपमेंट्स थे।

अधिकारी ने बताया कि जहाज के 10 सदस्यीय चालक दल में छह भारतीय हैं जबकि तुर्की और जॉर्जिया का एक-एक निवासी तथा दो सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। तुर्की की ओर से इस घटना पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

स्वार्ड शिप का किया था अपहरण

माना जा रहा है कि 8 समुद्री लुटेरे उस समूह के सदस्य थे, जिसने 26 अप्रैल को M/V स्वार्ड शिप का अपहरण किया था। अधिकारी ने बताया कि बाद में तुर्की के स्वामित्व वाले जहाज अपहृत शिप के पास पहुंचे, जबकि तुर्की के हेलीकॉप्टर और ड्रोन उस इलाके पर नजर रखे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दो लोगों को लेकर एक छोटी नाव उस शिप के पास पहुंची और मादक पदार्थ खत पहुंचाया, जिसे आमतौर पर सोमालिया में लोग नशे के लिए चबाते हैं।

चार लोगों की मौत

अधिकारी ने बताया कि नाव के लौटने के बाद हवाई हमला हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वालों और हताहतों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। अधिकारी ने बताया कि जहाज और चालक दल की मौजूदा स्थिति भी स्पष्ट नहीं है।

न : इमरान खान 6 घंटे के अंदर फिर पहुंचे जेल, हॉस्पिटल में टेस्ट कराकर भेज दिया वापस

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुसीबतों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। उन्हें फिर से वापस जेल भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार देर रात इमरान को कड़ी सुरक्षा में शिफा हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन महज 6 घंटे के अंदर ही मेडिकल जांच के बाद उन्हें फिर से अदियाला जेल वापस भेज दिया गया।

शहबाज शरीफ सरकार ने आज शुक्रवार सुबह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल से वापस अदियाला जेल पहुंचा दिया। उन्हें रावलपिंडी स्थित जेल से गुरुवार देर रात ही मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें जेल में ही भेज दिया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक, पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान को वापस उनकी कोठरी में ले गई।

इससे पहले, इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से शिफा हॉस्पिटल ले जाया गया था। जेल अधिकारियों के मुताबिक, इमरान को कड़ी सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल ले जाया गया। साथ ही, सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की कई बड़ी टुकड़ियां तैनात की गई थीं।

सूत्रों का यह भी कहना है कि हॉस्पिटल में PTI के संस्थापक इमरान के इलाज की व्यवस्था पूरी कर ली गई थी और उनकी मेडिकल जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई थी। इस हफ्ते की शुरुआत में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। 3 जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इमरान खान को अगले 48 घंटों के अंदर इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल ले जाया जाए। देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को यह निर्देश दिया था कि 73 साल के इमरान को अगले 2 दिन के अंदर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया जाए और 16 सितंबर के लिए निर्धारित अगली सुनवाई तक उन्हें वहीं रखा जाए। तब सरकार ने कहा था कि वह कोर्ट के आदेश को लागू करेगी, लेकिन बाद में उसकी ओर से शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आदेश पर पुनर्विचार और उसे वापस लेने का अनुरोध किया गया।

सरकार ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने समीक्षा याचिका पर कई आपत्तियां उठाईं और उसे वापस कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि याचिका बिना पूरे रिकॉर्ड के दायर की गई थी। यह याचिका इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त ने इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल के जरिए दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के इस मामले से जुड़े अंतरिम आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।

एफबीआई की वांटेड लिस्ट में भारतीय नागरिक कमल का नाम, वारंट जारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन!

वॉशिंगटन, एजेंसी। एफबीआई भारतीय नागरिक कमल की तलाश कर रही है, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य के तौर पर अंतरराष्ट्रीय अपराध में शामिल होने का आरोप है। FBI ने गुरुवार को बताया कि कमल को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन में कथित तौर पर शामिल होने के लिए वांटेड घोषित किया गया है, जो जबरन वसूली के जरिए व्यापार में बाधा डालने की साजिश में लिप्त था। फेडरल एजेंसी ने कहा, यह संगठन, 'लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप', भारत के पंजाब राज्य में शुरू हुआ और कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगहों पर सक्रिय था।

एजेंसी ने बताया कि कमल के ख़िलाफ 1 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। उस पर जबरन वसूली के जरिए व्यापार में बाधा डालने की साज़िश रचने का आरोप है। FBI के नोटिस में कहा गया है, अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है, तो कृपया अपने स्थानीय FBI ऑफिस, नजदीकी अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें, या आप tips।fbi।gov पर ऑनलाइन जानकारी दे सकते हैं। FBI ने संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है और पिछले कुछ महीनों में बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कमल के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट एक जुलाई 2026 को जारी किया गया था। यह वारंट कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी कोर्ट ने लॉस एंजिल्स में जारी किया।

क्रिप्टो, एआई और ऑनलाइन बेटिंग से कमाया पैसा...अब अमेरिकी चुनाव में बहा रहीं जेन अल्फा कंपनियां

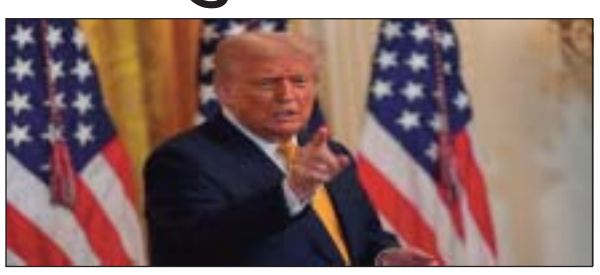

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले राजनीतिक चंदे और कॉरपोरेट खर्च का नया रिकॉर्ड बन रहा है। चुनावी फंडिंग में पारंपरिक वॉल स्ट्रीट, तेल और दवा कंपनियों की बजाय Gen Alpha कंपनियों के दखल में काफी इजाफा हो गया है। राजनीतिक फंडिंग में अब क्रिप्टोकरेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ी नई और Gen Alpha कंपनियां सबसे बड़े नए खिलाड़ी बनकर उभर रही हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी कंपनियों ने 2026 के हाउस और सीनेट चुनावों के लिए 15 महीनों के दौरान पहली तिमाही के अंत तक 51।7 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए हैं। यह 2024 के पूरे चुनावी चक्र में हुए 46।1 करोड़ डॉलर के पिछले रिकॉर्ड से भी अधिक है। नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले खर्च में और बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

पब्लिक सिटिजन के आंकड़ों के मुताबिक, 01 जनवरी 2025 से पहली तिमाही तक क्रिप्टो, टेक और ऑनलाइन गेमिंग उद्योगों ने मिलकर कम से कम 29।4 करोड़ डॉलर चुनावी राजनीति में लगाए। दरअसल, इन उद्योगों की कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों और नीतियों को समर्थन देना चाहती हैं, जो उनके सेक्टरों पर अपेक्षाकृत कम सख्त नियमन के पक्ष में हों।

सुपर PAC के जरिए बह रहा पैसा

क्रिप्टो, टेक और ऑनलाइन गेमिंग उद्योगों से जुड़ी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर सुपर PAC, उससे जुड़े PAC और तथाकथित डार्क मनी संगठनों का इस्तेमाल किया है। ऐसे संगठन बड़ी मात्रा में रकम जुटा सकते हैं। फिर, चुनावी विज्ञापन, मतदाता अभियान तथा रैलियों पर खर्च कर सकते हैं। हालांकि वे सीधे उम्मीदवारों को पैसा नहीं दे सकते । साथ ही चुनावी खर्च का समन्वय भी नहीं कर सकते हैं।

मस्क और ब्रिन भी बड़े दानदाता

रिपोर्ट के मुताबिक, SpaceX के संस्थापक एलन मस्क 2026 के संघीय चुनावों के लिए अब तक 9 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। वहीं, गुगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने कैलिफोर्निया में प्रस्तावित वेल्थ टैक्स सहित राज्य से जुड़े मुद्दों पर 10.6 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च किए हैं।मेटा ने भी कैलिफोर्निया, टेक्सास, इलिनॉय और अन्य राज्यों में दोनों दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले चार अलग-अलग सुपर PAC को 6।5 करोड़ डॉलर दिए हैं।

2024 में सफल रहा था क्रिप्टो का मॉडल

क्रिप्टो कंपनियों ने 2024 के चुनाव में भी भारी निवेश किया था। कॉइनबेस, रिपल और निवेश फर्म आंद्रेसेन होरोविट्ज जैसे बड़े नामों ने फेयरशेक सुपर PAC के जरिए चुनावी राजनीति में पैसा लगाया था। कंपनियों की यह रणनीति इतनी सफल हुई था।अ ब AI, बिग टेक और स्पोर्ट्स बेटिंग जैसे दूसरे उद्योग भी इसी मॉडल को अपना रहे हैं।

राजनीतिक विज्ञापनों पर 11.6 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान

एडइंपैक्ट के अनुमान के मुताबिक, 2026 के मध्यावधि चुनावों में कुल राजनीतिक विज्ञापनों पर 11.6 अरब डॉलर खर्च हो सकता है। यह 2023-24 के चुनावी चक्र के 11.2 अरब डॉलर के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगा।

अमेरिकी राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने का संकेत

अमेरिका मध्यावधि 2026 के चुनावों में क्रिप्टो, AI और ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों का बढ़ता दखल अमेरिकी राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने का एक संकेत है। कभी वॉल स्ट्रीट और तेल कंपनियां राजनीतिक फंडिंग की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थीं, लेकिन अब नई तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था से पैदा हुए अरबपति और कंपनियां अमेरिकी चुनावी राजनीति के नए किंगमेकर बनकर उभर रहे हैं।

वंदे मातरम् विवाद बोले कपिल सिब्बल- क्या मोदी ने मुख्यमंत्री और वाजपेयी ने पीएम रहते हुए पूरा गीत गाया?

नई दिल्ली, एजेंसी। वंदे मातरम् को लेकर विवाद बना हुआ है। केंद्र सरकार जहां कांग्रेस पर वंदे मातरम् का अपमान करने का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी के लोगों का नकली राष्ट्रवाद है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते कभी पूरा वंदे मातरम् गाया। या फिर वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते?

कपिल सिब्बल ने आज शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में लिखा, "अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमिटी के वंदे मातरम् के 2 पैरा गाने का फैसला राष्ट्र विरोधी है। मेरा सवाल है- क्या भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 1950 से लेकर अपने किसी प्राइवेट या आधिकारिक

कार्यक्रमों में पूरा पैरा गाया है? मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वंदे मातरम् का पूरा पैरा गया है? क्या वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते ऐसा किया? तब तो आप भी देश विरोध हो। आपकी वोट-बैंक की राजनीति का पर्दाफाश हो गया!"

तुष्टीकरण के लिए 'वंदे मातरम्' के 2 टुकड़े: शाह

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम् मामले पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वंदे मातरम् के सिर्फ दो पैरा ही गाने के पार्टी के फैसले का मकसद कानून की खुली अवहेलना कर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करना है। बीजेपी नेता ने राष्ट्र गीत को पूरा गाने की जगह सिर्फ दो पैरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमिटी (सीडब्ल्यूसी) के फैसले का जिक्र करते हुए देश के विभाजन के इतिहास का जिक्र किया और कहा कि वंदे मातरम् के टुकड़े करने के कारण ही देश को इसके परिणाम भुगतने पड़े।

उन्होंने सोशल मीडिया X पर कहा, "कांग्रेस ने ही 1937 में तुष्टीकरण के लिए 'वंदे मातरम्' के 2 टुकड़े किए। वहीं से दो-राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और देश का विभाजन हो गया। लेकिन वंदे मातरम् के 150वें वर्ष पर (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर है।" उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् के टुकड़े करने की गलती एक बार हो चुकी है और देश परिणाम भी भुगत चुका है।।

बीजेपी के लोग नकली राष्ट्रवादी: कांग्रेस

दूसरी ओर, कांग्रेस ने वंदे मातरम् को लेकर अमित शाह द्वारा निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी छात्रों और राम मंदिर से जुड़ी चंदा चोरी जैसे अहम विषयों से ध्यान भटकाना चाहती है और इसे के लिए राष्ट्र गीत को लेकर विवाद खड़े करना चाहती है, जबकि उसके लोग झूठे और नकली राष्ट्रवादी हैं। पार्टी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ट्राइड (परखे जा चुके) और टायर्ड (थक चुके) हैं तथा अब उन्हें जल्द ही रिटायर हो जाना चाहिए। रमेश ने दावा किया कि पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और बीजेपी छात्रों के मुद्दे तथा राम मंदिर से चंदा चोरी तथा आस्था के साथ धोखा जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस उनके जाल में फंसने वाली नहीं है।

तेलंगाना सीएम रेड्डी को अमेरिका जाने की नहीं मिली इजाजत, लंदन से लौटेंगे हैदराबाद

नई दिल्ली, एजेंसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को केंद्र सरकार से अमेरिका जाने की इजाजत नहीं मिली है। रेड्डी 23 अगस्त को लंदन से हैदराबाद वापस आ जाएंगे। उन्हें अमेरिका के बॉस्टन जाना था। राज्य सरकार ने पॉलिसी और प्रोटोकॉल के तहत UK और USA की यात्रा के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी थी, लेकिन सिर्फ UK यात्रा को ही मंजूरी मिली। केंद्र ने राज्य सरकार को अनुमति न देने की जानकारी तब दी, जब आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल UK पहुंच चुका था।

केंद्र के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, इस दौरे का एकमात्र मकसद केंद्र की नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया के बेहतरीन संस्थानों को भारत, तेलंगाना और हैदराबाद में लाना था। ये संस्थान हमारे युवाओं की उन आकांक्षाओं को पूरा करते, जिनके तहत वे बेहतरीन आइवी लीग और दुनिया के शीर्ष संस्थानों से शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि जब देश के निर्माण और युवाओं के भविष्य की बात आती है, तो हम सभी को राजनीति और चुनावों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र के फ़ैसले को मानते हुए लंदन से भारत लौटने का फ़ैसला किया है। वे बॉस्टन जाने के बजाय हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे USA की यात्रा जारी रखें और सभी MoU (समझौता ज्ञापन) और पार्टनरशिप एग्रीमेंट पूरे करें। रेड्डी वर्तमान में लंदन में हैं। यहां से उनकी योजना अमेरिका जाने और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटने की योजना थी। सीएम ऑफिस ने कहा कि मुख्यमंत्री ए। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाले आधिकारिक तेलंगाना-राइजिंग प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका का दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। मंत्रालय ने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस (अमेरिका) यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई है। इसने कहा कि रेड्डी अमेरिका के बॉस्टन जाने के बजाय 23 अगस्त को लंदन से हैदराबाद लौटेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री को अगले हफ्ते अमेरिका जाना था, जहां वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी) के परिसर का दौरा करते। उनका 25 अगस्त को बॉस्टन में वर्जीनियां टेक यूनिवर्सिटी के एक दल के साथ संवाद का कार्यक्रम था। राज्य सरकार के अनुसार, ब्रिटेन में रेड्डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावत्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एवं अमीरात स्टेडियम जाने का कार्यक्रम है।

अंजलि अरोड़ा को माता सीता के किरदार में देख छिड़ी बहस, यूजर्स बोले- सीता के रोल में सूर्पनखा

कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में कास्ट किए जाने पर सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज हैं। वह कमेंट सेक्शन के जरिए फिल्म की कास्टिंग और विजुअल इफेक्ट्स की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

कंटेंट क्रिएटर अंजलि अरोड़ा फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' से अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म का टीजर और पोस्टर मेकर्स ने मंगलवार को रिलीज किया। इसके बाद से ही एक्ट्रेस की कास्टिंग को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई।

यूजर्स कर रहे कास्टिंग का विरोध

फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में अंजलि अरोड़ा सीता और देव शर्मा राम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया, जिसमें अंजलि को माता सीता के रूप में देखने के बाद यूजर्स भड़क उठे। अब वो इस फिल्म का और इसमें अंजलि को कास्ट किए जाने पर नाराजगी जता रहे हैं।

इस मामले पर अंजलि को सोशल मीडिया में बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करने पड़ रहा है।

एक यूजर ने लिखा, 'मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन सीता माता के किरदार के लिए यह गलत कास्टिंग है।'

दूसरे यूजर ने कमेंट किया- 'मां सीता के रोल में सूर्पनखा?'

इस फिल्म की तुलना फिल्म 'आदिपुरुष' से करते हुए यूजर ने लिखा, 'आदिपुरुष को सलाम।'

वहीं अन्य यूजर्स ने इसे तीन घंटे की इंस्टाग्राम रील बताया।

विजुअल इफेक्ट्स की भी आलोचना

फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही अलग-अलग कारणों से इसकी आलोचना हो रही है। फिल्म की कास्टिंग के अलावा टीजर में दिखाए गए वीएफएक्स भी दर्शकों को कमजोर दिखाई दिए। कई यूजर्स ने इन वीएफएक्स को शर्मनाक बताया। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की प्रस्तुती और म्यूजिक भी यूजर्स को उत्साहित नहीं कर सका।

फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के बारे में

इस फिल्म का निर्माण महोबिया फिल्म्स के बैनर तले हुआ है। फिल्म को प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने प्रोड्यूस किया है। अजय कनौजिया की कंपनी एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ने इसे पेश किया है। इसका निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है। फिल्म में अंजलि के अलावा शील वर्मा, रजनीश दुग्गल और निर्भय वाधवा भी अहम किरदारों में हैं।

पैसा और प्यार में से किसको चुनेंगी निया शर्मा? टीवी अभिनेत्री ने दिया दो-टूक जवाब, फैंस ने भी दी प्रतिक्रिया

निया शर्मा टीवी की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जो अपने बोल्ड लुक और बयानों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में निया शर्मा ने बताया कि वह प्यार और पैसे में से किसका चुनाव करेंगी?

निया शर्मा को टीवी सीरियल 'जमाई राजा' और 'नागिन 4' के जरिए घर-घर पहचान मिली थी। इसके अलावा वह कई रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी हैं। हाल ही निया 'लाफ्टर शेफ' के सेट पर नजर आईं। यहां पैपराजी ने उनसे सवाल किया कि वह प्यार और पैसे में से किसे चुनेगी? इस पर क्या रहा अभिनेत्री का जवाब, जानिए?

पैसे और प्यार में से निया ने किसे दी अहमियत?

पैपराजी के सामने निया शर्मा नारंगी रंग के सूट-सलवार में आईं। वह 'लाफ्टर शेफ' का एपिसोड शूट करने आई थीं। इस सेट पर उन्होंने पैपराजी को कहा, 'वह प्यार और पैसे मे से पैसे को चुनेंगी।' वह आगे कहती हैं, 'वह हमेशा पैसे को ही चुनेंगी।'

फैंस ने अभिनेत्री के जवाब पर क्या प्रतिक्रिया दी?

जब फैंस ने निया शर्मा जवाब सुना तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें सही बताया। इसके अलावा कुछ फैंस ने निया के लुक को सराहा और हार्ट इमोजी शेयर किए। निया शर्मा की इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उनके लगभग 8 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं।

क्या होगा निया शर्मा का अगला प्रोजेक्ट?

'नागिन 4' में निया शर्मा ने लीड रोल किया था। अब तक इस टीवी शो के सात सीजन आ चुके हैं, जिनमें मौनी रॉय के अलावा, सुरभि ज्योति, सुरभि चांदना, अदा खान, तेजस्वी प्रकाश और प्रियंका चाहर चौधरी ने लीड रोल किए थे।

बीते दिनों इस शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने एक वीडियो में सभी अभिनेत्रियों की झलक दिखाई है। साथ ही बताया कि वह इसे टीवी से आगे लेकर जाना चाहती हैं। हालांकि, एकता कपूर ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह 'नागिन' पर कोई फिल्म बनाएंगी या वेब सीरीज।

एक्शन ड्रामा भोगी के साथ लौट रहे शर्वानंद, 28 अगस्त 2026 को रिलीज होगी फिल्म

साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता शर्वानंद जल्द ही एक्शन-ड्रामा फिल्म भोगी लेकर आ रहे हैं। फिल्म के निर्माताओं ने बुधवार को इसका पहला लुक पोस्टर जारी किया और साथ ही रिलीज डेट भी बताई। अभिनेता शर्वानंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्ट किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, कुछ आग ऐसी होती है, जो जलाती नहीं, बल्कि सच सामने लाती है।

फिल्म भोगी एक जबरदस्त और जोशीला शरवा संपथ ब्लड फेस्ट है। भोगी 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह फिल्म 1960 के दशक के उथल-पुथल भरे समय पर आधारित होगी। फिल्म को नॉर्थ तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर के एक गांव की पृष्ठभूमि पर बनाया गया है।

फिल्म की खास बात है कि इसमें दो अभिनेत्रियां नजर आएंगी। जहां अनुपमा परमेश्वरन लीडिंग लेडी के रोल में होंगी, वहीं डिंपल हयाती भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगी। यह शर्वानंद के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म में वे निर्देशक संपत नंदी के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही, यह उनकी पहली पैन-इंडिया फिल्म है।

यह एक बड़े बजट वाली फिल्म है, जिसमें शानदार तकनीकी टीम काम कर रही है। प्रोडक्शन डिजाइन किरण कुमार मन्ने ने किया है, सिनेमैटोग्राफी सौंदर राजन एस ने की है, और म्यूजिक भीम्स सेसिरोलियो ने कंपोज किया है। यह शर्वानंद की 38वीं फिल्म है, जिसमें वे एक दमदार अवतार में दिखेंगे। उन्होंने 2004 में फिल्म ऐंधो तारीखू से शुरुआत की और प्रस्थानम, रन राजा रन, मल्ली मल्ली इदी रानी रोजु और शतमानम भवति जैसी सफल फिल्मों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com